

गाड़ियों का देर से पहुंचना

११०५. श्री कृष्ण देव त्रिपाठी : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छै महोनों में मुगलसराय से लखनऊ होती हुई कानपुर जाने वाली आई० एम० एल० सी० सवारी गाड़ी कितनी बार लखनऊ व कितनी बार कानपुर देर से पहुंची; और

(ख) इस अवसर पर होने वाली देरी का कारण क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) पिछले ६ महोनों में, अर्थात् फरवरी से जुलाई, १९६२ तक नं० १ एम० एल० सी० सवारी गाड़ी लखनऊ में ६१ बार और कानपुर में १११ बार देर से पहुंची ।

(ख) इस गाड़ी के देर से चलने के मुख्यतः दो कारण हैं, खतरे की खंजीर का खींचा जाना और दूसरी गाड़ियों के देर से चलने के कारण निर्धारित स्थान पर गाड़ियों का क्रासिंग न होना ।

गाड़ियों का देर से चलना

११०६. श्री कृष्ण देव त्रिपाठी : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे की बालामऊ-कानपुर के बीच चलने वाली गाड़ी पिछले छै महीने में कितनी बार कानपुर और बालामऊ से निर्धारित समय से देरी से चली तथा देरी से पहुंची; और

(ख) इसके क्या कारण थे ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) पिछले ६ महीनों में अर्थात् फरवरी से जुलाई, १९६२ तक बालामऊ और कानपुर के बीच चलने वाली नं० १ बी०सी०, २ बी० सी०, ३ बी० सी० और ४

बी० सी० सवारी गाड़ियां जितनी बार बालामऊ और कानपुर स्टेशनों से देर से चलीं और देर से पहुंचीं उसका व्यौरा इस प्रकार है :

	जितनी बार देर से चली बालामऊ से	जितनी बार देर से पहुंची कानपुर में
१. बी० सी .	११	६०
३ बी० सी० .	५१	४८
	कानपुर से	बालामऊ में
२. बी० सी०	५३	४३
४. बी० सी०	५६	६१

(ख) १ बी० सी० सवारी गाड़ी बालामऊ से आम तौर पर ठीक समय पर छूटती रही । यह गाड़ी बहुत कम बार देर से रवाना हुई । नं० ३ बी० सी० सवारी गाड़ी बालामऊ से देर से छूटती रही । जब ३७६ डाउन दिल्ली-इलाहाबाद सवारी गाड़ी देर से आतो थी, तो अधिकतर उसका मेल लेने के लिये नं० ३ बी० सी० सवारी गाड़ी देर से छूटती रही । नं० २ बी० सी० और ४ बी० सी० सवारी गाड़ियां ठीक समय पर छूटें, इसके लिये कार्रवाई की जा रही है ।

टीकमगढ़ में गन्ने का उत्पादन

११०७. श्री मात : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टीकमगढ़ (म० प्र०) में गन्ने की वार्षिक कितनी पैदावार है ;

(ख) क्या यह सब है कि वहां पर चीनी बनाने का कोई मिल नहीं है ;

(ग) क्या सरकार वहां गन्ने को पैदावार को देखते हुए चीनी मिल खोलने का विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अ० म० बामस) : (क) १९६०-६१ में लगभग ४२,००० टन ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). इस सम्बन्ध में कोई धावेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ, शायद इसलिये कि उस जिले में उत्पन्न गन्ना, आर्थिक आकार की चीनी की फैक्ट्री खोलने के लिये पर्याप्त नहीं है। तथापि चीनी के अधिक उत्पादन को दृष्टि में रखते हुए चीनी उद्योग में और लाइसेंसिंग क्षमता अभी रोक दी गई है।

बीना-कोटा रेल मार्ग पर मूंगावली में विश्राम गृह

११०८. श्री माते : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीना-कोटा लाइन पर मूंगावली स्टेशन पर विश्राम-गृह नहीं है ; और

(ख) क्या सरकार वहां पर विश्राम-गृह बनाने का विचार कर रही है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री शाह-नवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) इस स्टेशन पर आने-जाने वाले यात्रियों की संख्या को देखते हुए यहां विश्राम-लय बनाने का औचित्य नहीं है।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज

११०९. श्री माते : क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में मध्य प्रदेश में कितने टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की योजना है ;

(ख) उसमें से कितने एक्सचेंज टीकमगढ़, छतरपुर और भोपाल जिलों में खोले जायेंगे ; और

(ग) क्या सरकार बलुगढ़, खरणपुर झलकनगर, पलेरा और चन्देरी में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने पर विचार कर रही है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमन्त्री

(श्री भगवती) : (क) ७१।

(ख) टीकमगढ़-कुछ नहीं।

छतरपुर १

सीहोर (भोपाल) ४

(ग) टेलीफोन एक्सचेंज की कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है और ऐसे कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

National Water Supply and Sanitation Programme

1110. Shri Tan Singh: Will the Minister of Health be pleased to state:

(a) the amount of subsidies given by the Central Government to Rajasthan during the year 1958-59, 1959-60, 1960-61 and 1961-62 under the National Water Supply and Sanitation Programme;

(b) the amount actually spent during each of these years; and

(c) the amount allotted in the Third Five Year Plan for Rajasthan under the above programme?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) According to the existing procedure for the release of Central Assistance to the States, allotment of funds is not made scheme-wise but the amount is sanctioned only at the end of each year for broad groups or categories of schemes. Three fourths of the total Central Assistance allocated for a financial year is, however, released in lumpsum ways and means advances to the State Governments in nine equal instalments during the course of the year. In view of this position, the question of sanctioning assistance specifically for the National Water Supply & Sanitation Programme (Rural) does not arise.

(b)

Year	Amount spent (Rs. in lakhs)
1958-59	27.76
1959-60	55.00
1960-61	58.18
1961-62	64.00

(c) Rs. 200.00 lakhs.

Urban and Rural Water Supply in Rajasthan

1111. **Shri Tan Singh:** Will the Minister of Health be pleased to state:

(a) whether the Central Government have advised the Rajasthan Government to set up Urban and Rural Assessment Committees for making complete and correct assessment of the problem of water and for facilitating a realistic planning in the future years;

(b) the specific functions of the Committees;

(c) the time by which the committees will be expected to function; and

(d) the measures to be taken by the Central Government for Urban and Rural Water Supply pending a comprehensive and correct assessment of the problem by the State Committee?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) and (c). The Report of the National Water Supply and Sanitation Committee containing the recommendation with regard to the setting up of Urban and Rural Assessment Committees has been forwarded, among others, to the Government of Rajasthan on the 30th May, 1962. The reply of the State Government in the matter has not, so far come in. As far as we are aware, no Assessment Committee has yet been formed.

(b) The specific functions of the Committees are contained in paragraph 57 of the Report of the National Water Supply and Sanitation Committee which has already been laid on the Table of the Sabha.

(d) The State Governments have been asked to set up Special Investigation Divisions with 100% grant from the Central Government. A proposal for setting up a Non-statutory Drinking Water Board in the Union Health Ministry is under consideration.

परिवार नियोजन केन्द्र

१११२. श्री कृष्ण देव त्रिपाठी : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन के कितने दवाखाने इस समय देश में हैं ;

(ख) उत्तर प्रदेश के गागीण व शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग कितने दवाखाने हैं तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक कितने हो जाने की सम्भावना है ; और

(ग) अब तक उत्तर प्रदेश के परिवार नियोजन केन्द्रों से कितने व्यक्तियों ने किस प्रकार की मदद ली है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :

(क) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में जून १९६२ के अन्त तक गर्भ-रोधकों का वितरण करने वाले ४१६ नगर एवं १,८८४ ग्राम मेडिकल स्वास्थ्य केन्द्रों के अतिरिक्त ६४१ नगर परिवार नियोजन केन्द्र तथा १,३५८ ग्राम परिवार नियोजन केन्द्र थे ।

(ख) ३१ मार्च, १९६२ तक की सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में २५३ (५६ नगर एवं १९४ ग्राम) परिवार नियोजन केन्द्र कार्य कर रहे थे । लक्ष्य संख्या क्या है इसके बारे में सूचना एकत्र की जा रही है ।

(ग) उत्तर प्रदेश के परिवार नियोजन केन्द्रों की गर्भ-रोधक वितरण जैसी परिवार नियोजन सेवाओं का १६६,३६५ व्यक्तियों ने उपयोग किया ।

उत्तर प्रदेश के गांवों में बिजली लगाना

१११३. श्री कृष्ण देव त्रिपाठी : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक उत्तर प्रदेश में कितने गांवों में बिजली की सुविधा पहुंच चुकी है ;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के समाप्त होने पर इनकी क्या संख्या होगी ; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस पर कितनी धनराशि खर्ची गई है तथा अब तक कितनी खर्च हो चुकी है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अल्लगेशन) : (क) मार्च, १९६१ के अन्त तक ४,१४८ ग्रामों में बिजली लगाई गई थी। अप्रैल, १९६१ से २२३ और ग्रामों में बिजली लगाने की स्वीकृति मिल गई है।

(ख) ५,६४८।

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में ग्राम विद्युतन के लिये ६०० लाख रुपये का प्रबन्ध किया गया है। ऐसी सूचना मिली है कि तृतीय योजना के प्रथम वर्ष में ५७.४७ लाख रुपये व्यय हुए हैं।

हाल्ट स्टेशनों पर यात्री सुविधायें

१११४. श्री कृष्ण देव त्रिपाठी : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल्ट स्टेशनों पर यात्रियों के घूप और वर्षा से बचने के लिये क्या सुविधा प्रदान की गई है ;

(ख) यदि ऐसी कोई सुविधा नहीं है, तो क्या रेल विभाग शीघ्र यात्रियों को घूप और वर्षा से बचने के लिये उचित सुविधायें देने की व्यवस्था करेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह-नवाज खां) : (क) रेलवे की यह नीति है कि हाल्ट स्टेशनों पर यात्रियों के लिए एक छोटा सा प्रतीक्षा शेड बनाया जाय जिससे टिकट घर का काम भी लिया जाय। यह व्यवस्था सभी हाल्ट स्टेशनों पर की जा रही है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

कानपुर-लखनऊ बड़ी लाइन को दोहरा करना

१११५. श्री कृष्ण देव त्रिपाठी : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लखनऊ कानपुर के बीच बड़ी लाइन दोहरी करने का काम कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(ख) क्या कानपुर के निकट गंगा नदी पर भी दोहरी लाइन डालने के लिये सरकार एक पुल और बनाने पर विचार कर रही है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) कानपुर और लखनऊ के बीच ४४.५ मील लम्बे सेक्शन में से कानपुर और उन्नाव के बीच ६.६० मील लम्बे टुकड़े पर (जिसमें गंगा का पुल शामिल नहीं है) दोहरी लाइन बिछायी हुई है। इस सेक्शन के बाकी इकहरी लाइन के टुकड़े पर दोहरी लाइन बिछाने का विचार नहीं है।

(ख) कानपुर के पास गंगा पर एक और पुल बनाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्तर प्रदेश में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

१११६. श्री कृष्ण देव त्रिपाठी : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मलेरिया उन्मूलन योजना को उत्तर प्रदेश में कितनी सफलता मिली है ;

(ख) पिछले पांच वर्ष में प्रतिवर्ष कितने व्यक्ति उत्तर प्रदेश में मलेरियाग्रस्त हुए तथा कितनी मौतें हुई ;

(ग) यह योजना उत्तर प्रदेश में कितने वर्ष और चलेगी ; और

(घ) योजना समाप्त होने पर क्या मलेरिया का पूर्ण उन्मूलन हो जायेगा ?

स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर) :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम १९५३-५४ में प्रारम्भ किया गया था। ५ वर्ष की एक सक्रियावस्था के पश्चात् यह देखा गया कि मलेरिया की व्यापकता काफी घट गई है, जैसा कि निम्न-

कित मलेरियोमीट्रिक सूचक से स्पष्ट होगा।

वर्ष	बाल प्लीहा वहण	बाल परजीवी दर	शिशु परजीवी दर
१९५३-५४.	१३.६	५.४	०.४
१९५७-५८.	७.४	०.६	०.३

१९५३-५४ में उपलब्ध आंकड़ों की तुलना में बाल प्लीहा, परजीवी और शिशु परजीवी दरों में क्रमशः ४५.६, ८८.९ और २५ प्रतिशत तक कमी हुई है। अनुपाती रोगी दर (अस्पतालों और औषधालयों में इलाज किये गये सभी प्रकार के रोगों के रोगियों से क्लिनिकी मलेरिया रोगियों का प्रतिशत) जो १९५३-५४ में १४.९ प्रतिशत थी, १९५७-५८ में वह ७.१ प्रतिशत जात हुई, अर्थात् इसमें लगभग ५२.३ प्रतिशत कमी हुई। मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम १९५८-५९ में उन्मूलन कार्यक्रम में बदल दिया गया। उन्मूलन कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में ४० एकक (प्रत्येक दस लाख आबादी की) स्थापित की गई। १९५९-६० से २७ दूसरी मलेरिया उन्मूलन एककों ने काम करना प्रारम्भ कर दिया जिससे सारे राज्य में कुल ६७ एकके हो गईं। मलेरिया की घटनायें और भी काफी कम हो गई हैं। १९६१-६२ के अन्त में अनुपाती रोगी दर ०.९ प्रतिशत

थी जबकि यही दर १९५७-५८ में ७.१ प्रतिशत तथा १९५३-५४ में १४.९ प्रतिशत थी। इस प्रकार १९५३-५४ में उपलब्ध आंकड़ों की तुलना में १९६१-६२ में कुल ९४ प्रतिशत कमी हुई। इसके अतिरिक्त बाल प्लीहा, बाल परजीवी और शिशु परजीवी सूचक में काफी कमी हुई है। यह प्रतीत किया गया है कि १९५३-५४ के आंकड़ों की तुलना में १९६०-६१ तक प्लीहा, परजीवी और शिशु परजीवी सूचकों में क्रमशः कुल ९६.३, ९९.८ और ९२.५ प्रतिशत कमी हुई है।

(ख) यह ज्ञात किया जा सकता है कि देश में मोतों के पंजीयन की वर्तमान प्रणाली के अनुसार मरण सम्बन्धी विश्वस्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अस्पतालों तथा औषधालयों में सिर्फ मलेरिया निदान किये गये रोगियों के अस्वस्थता-आंकड़े ही उपलब्ध हैं। ये आंकड़े भी हर वर्ष के राज्य भर के उपलब्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे आंकड़े देने वाले औषधालयों की संख्या भी हर वर्ष अलग-अलग होती है। इन कमियों के कारण मलेरिया अस्वस्थता में कमी भिन्न भिन्न वर्षों के अनुपाती मलेरिया मामलों (सब प्रकार के रोगियों की कुल संख्या से मलेरिया के रोगियों का प्रतिशत) की तुलना द्वारा ही प्राप्त करनी पड़ती है।

गत पांच वर्षों में इलाज किये गये सभी प्रकार के रोगों के रोगियों एवं क्लिनिकल मलेरिया के रोगियों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	सब रोग	क्लिनिकल मलेरिया के रोगी	अनुपाती रोगी दर प्रतिशत
१९५७-५८ .	३,५५०,६२२	२५३,४१८	७.१
१९५८-५९ .	४,९२७,९१४	२६८,८७२	५.५
१९५९-६० .	५,७९४,२९४	२८७,०३५	३.३
१९६०-६१ .	१०,१२८,८१९	१९२,०७६	१.९
१९६१-६२ .	१२,८६०,८६९	११३,४८९	०.९

(ग) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में तृतीय पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक जारी रहेगा।

(घ) आशा है कि वर्तमान प्रगति के साथ तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक मलेरिया का उन्मूलन हो जायेगा। तब इस कार्यक्रम का, नेपाल जैसे अन्य देशों की सीमा के पास स्थित एककों के अलावा राज्य के प्रमुख भाग में प्रबन्धात्मक पहलू प्रारम्भ होगा।

Dam at Mainadhar on Barak River, Assam

1117. **Shri N. E. Laskar:** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 196 on the 7th August, 1962 and state:

(a) who are the investigating authority and the name of the experts engaged in the investigation of earthen dam at Barak river at Mainadhar, Assam;

(b) the year in which the investigation was actually started; and

(c) the probable date by which Government is expecting to complete the investigation?

The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Alagesan): (a) The investigations are being carried out by the Central Water & Power Commission.

(b) and (c). The preliminary investigations to explore the possible dam sites on the Barak river in Assam were carried out by the Central Water & Power Commission as far back as 1954, but none of the sites investigated for a dam was considered suitable, except the one at Mainadhar, which held some promise. Some foundation explorations were also carried out at this site. After examining the cores obtained from this site, the Geologist gave the opinion that the site was quite unsuitable for any masonry or concrete

dam. Further investigation work was stopped at the end of January, 1957.

In a meeting of the State Flood Control Board held on 20-2-58, the Agriculture Minister, Assam suggested reconsideration of a storage project on the river Barak. A Member of the Central Water and Power Commission and the Chief Engineer, (Floods), Central Water and Power Commission and the Chief Engineer, Irrigation and Flood Control, Assam alongwith the Geologist inspected the Mainadhar dam site on the 18th of January, 1960. As a result of this joint inspection, it was considered that an earth dam of a moderate height of 200 to 250 ft., solely for flood control, might be practicable at the site and that further investigations might be carried out to establish the suitability of the site for the proposed earth dam. At the request of the Government of Assam, the Central Water and Power Commission have taken up the necessary investigations of the site. The work was started on 1-4-60 and most of the investigation work has been done. The remaining drilling work is expected to be completed by 31-3-1963.

Power Stations in Bilonia, Sunamera and Kamalpur

1118. **Shri Biren Dutta:** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

(a) whether power stations are proposed to be built in Bilonia, Sunamera and Kamalpur; and

(b) if so, when these are expected to be started?

The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Alagesan): (a) and (b). These places are proposed to be electrified by extending supply from the neighbouring generating stations. Construction of the necessary transmission lines and sub-stations is likely to be started during the current financial year.

**Engines Running on N.G. Line
Between Nampada and
Gunupur**

1119. Shri Ulaka: Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1664 on the 22nd May, 1962 and state:

(a) the circumstances under which the old light engines on the narrow gauge line between Nampada and Gunupur could not be repaired till now;

(b) whether Government have considered to provide new light engines on the said narrow gauge line;

(c) if so, when; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan): (a) No locomotive working on this section had been unnecessarily detained for repairs or for materials for any considerable length of time.

(b) and (c). Not for the present.

(d) The policy is to replace stock only when their condition warrants it.

Doikhal Railway Station (Orissa)

1120. Shri Ulaka: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Doikhal Railway Station (Orissa) is not provided with medical facilities;

(b) whether it is also a fact that the staff of Doikhal Railway Station are undergoing much difficulties for want of a dispensary on the premises of the platform at Doikhal or within six miles radius of Doikhal railway station; and

(c) if so, the action taken or proposed to be taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan): (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Telephone for Panchayat Samithi Offices

1121. Shri Ulaka: Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state:

(a) whether Government have received any proposal from the Orissa Government to provide telephones in each of the Panchayat Samithi offices in Orissa;

(b) if so, the number of panchayat samithis to which telephones have already been provided;

(c) the number of panchayat samithis which have not yet been provided with telephones; and

(d) when the above Panchayat samithis are expected to be provided with telephones?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Communications (Shri Bhagavati): (a) Yes.

(b) 143 already provided with telephone facilities. Sanction for 16 more issued.

(c) 164.

(d) Telephones will be provided if proposals are remunerative or the State or any other party agrees to the rent and guarantee terms.

Over-Bridge at Parvatipuram

1122. Shri Ulaka: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether Government have received any representation from the public for the construction of an over-bridge at the Railway level crossing at Parvatipuram (Andhra Pradesh); and

(b) if not, whether Government have any proposal for the construc-

tion of a bridge at the said level crossing?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy): (a) No, Sir.

(b) Schemes for over/under-bridge in replacement of existing level crossings have to be sponsored by the State Government. The Railways undertake such works when the State Governments recommend and also provide necessary funds to meet their share of the cost, as per extant rules. There has been no firm proposal so far, from the Government of Andhra Pradesh for a road over-bridge in place of the existing level crossing at Parvatipuram, during the Third Five Year Plan.

P.O. Building Parlakhemedi (Orissa)

1123. Shri Ulaka: Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that the sub-post office building at Parlakhemedi (Orissa) is very old and may collapse at any time;

(b) if so, whether Government are considering to construct a new building in its place;

(c) if so, when; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Communications (Shri Bhagavati): (a) Yes.

(b) Yes.

(c) The land on which the existing building stands is not sufficient to meet the present requirements of the Post Office. Additional land is being acquired for putting up a new building and the matter has been taken up with the Revenue authorities. The new building will be constructed after the necessary formalities have been completed. In the meantime the Post Office is being shifted temporarily to a rented build-

ing for carrying out repairs to the existing building.

(d) Does not arise.

Railway Lines in Andhra Pradesh

1124. Shri Ulaka: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that investigations have been made to lay a broad gauge line ex. Palasa to Vizianagaram (Andhra Pradesh) via Parlakhemedi (Orissa);

(b) if so, whether Government have considered to extend the said broad-gauge line upto Gunupur (Orissa) and then divert it into Andhra Pradesh; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy): (a) In connection with the survey for the proposed doubling of the Palasa-Vizianagaram section, investigations are being made to lay the second line on a retired alignment with the object of obtaining a line which will generally be free from likely flood damages. Whether this alignment will go via Parlakhemedi will be known only after the survey has been completed and the report has been examined.

(b) No.

(c) The retired alignment will go in the interior only to the extent needed for making it free from likely flood damages. It is not considered necessary to take the line via Gunupur for achieving this objective.

Electrification of Kashinagar (Orissa)

1125. Shri Ulaka: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that the railway station at Kashinagar (Orissa) is not yet electrified even though it has become an important station on the narrow gauge line between Navapada and Gunupur;

(b) if so, when it is expected to be electrified;

(c) whether it is also a fact that Kashinagar railway station does not have any waiting room for upper class passengers; and

(d) if so, when a waiting room for upper class passengers would be constructed?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawas Khan): (a) and (b). Kashinagar station is a wayside station on the narrow gauge Parlakamedi Light Railway and has not been electrified yet. In consultation with the Passenger Amenity Committee, this work is programmed during 63-64.

(c) Yes.

(d) The average number of upper class passengers dealt with per day at this station is only one which does not justify provision of an upper class waiting room.

Ramanadhi Dam, Madras State

1126. Shri M. P. Swamy: Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a draft scheme regarding Ramanadhi Dam in Tirunelveli District of Madras State has been received for Central Government's consideration from the Government of Madras;

(b) if so, the details of the scheme; and

(c) whether Government have agreed to the proposed scheme?

The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Alagesan): (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

Cancer

1127. { Shri Indrajit Gupta:
Shri Mohammad Elias:
Shri M. K. Kumaran:

Will the Minister of Health be pleased to state:

(a) whether a bovine bile derivative for treatment of inoperable cases of cancer has been discovered by Prof. Penn of U.S.A. working in collaboration with Indian doctors;

(b) whether experiments with the drug have proved successful;

(c) whether Prof Penn has asked Government for assistance to carry out further experiments in India; and

(d) Government's reaction thereto?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) and (b). Prof. Penn has been carrying out some research with his new drug in India in collaboration with Indian doctors. He has visited India twice and he claims that the results of his experiments are encouraging.

(c) and (d). Prof. Penn had only asked for facilities for research in this country and these have already been given to him.

Import of Chemical Fertilizers

1128. { Dr. P. N. Khan:
Shri Subodh Hansda:
Shri Basumatari:
Shri S. C. Samanta:

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have imported or are importing from U.S.A. a large quantity of chemical fertilizers of different varieties to mitigate the current deficit;

(b) if so, the total quantity of fertilizers imported or proposed to be imported;

(c) what are the modes of payment of the price of fertilisers; and

(d) by what time the amount will be paid?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Yes.

	Tonnes
(b) Sulphate of Ammonia	3,33,700
Nitrophosphate	15,000
Ammonium Phosphate	30,000
Total :	3,78,700

(c) The U.S. Government first issues a letter of commitment, against which the India Supply Mission, Washington opens irrevocable letters of credit which are operated upon by the Suppliers by presenting requisite shipping and other documents to the bank concerned.

(d) By March, 1963.

Road Transport Corporations

1129. Shri P. R. Chakraverti: Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state:

(a) whether all the States have set up Road Transport Corporations;

(b) the provision in terms of which these have been constituted;

(c) steps taken by Government in persuading the defaulting States to fall in line with others; and

(d) total amount of income-tax paid by these Corporations in 1961?

The Minister of Shipping in the Ministry of Transport and Communications (Shri Raj Bahadur): (a) Road Transport Corporations have so far been set up in the States of Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Maharashtra, Mysore, Madhya Pradesh, Punjab (Pepsu and Mandi-Kulu Areas) and West Bengal only.

(b) These Corporations have been constituted under the Road Transport Corporations Act, 1950.

(c) The plan provisions for expansion of the nationalised road transport undertakings in the different States are agreed to only on the condition that the States concerned will set up Road Transport Corporations or the management of these Undertakings. The matter is also under correspondence, between the States who have not set up Corporations so far and the Planning Commission.

(d) An amount of Rs. 1,47,28,247.00 was paid during the calendar year 1961 by way of income-tax. This includes the advance tax payments for the years 1961-62 and 1962-63 and payments due in respect of some earlier years.

Door-to-Door Delivery of Goods

1130. Shri P. R. Chakraverti: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether the system of door to door delivery of goods received and despatched through the Railways has started working;

(b) if so, when and in which places;

(c) whether the collection and delivery services are done through contractors;

(d) if so, the commission or service charges that are paid to them; and

(e) how far the public have reacted favourably to this new scheme?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy): (a) Yes.

(b) A statement giving the information is laid on the Table of the House. [See Appendix II, annexure No. 11].

(c) Yes.

(d) No commission is paid to the contractors, but they are generally paid the notified charges as are collected from the public for this service.

(e) The public response to the service is generally satisfactory.

Expert Team on Irrigation Projects

1131. { Shri Subodh Hansda:
Shri S. C. Samanta:
Shri B. K. Das:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri Surendra Pal Singh:
Shri R. S. Pandey:

Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have appointed expert team to find out the bottlenecks in construction of irrigation projects;

(b) if so, what are the reasons for slow progress of construction;

(c) whether the Committee have visited all the States; and

(d) whether they have submitted any report?

The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Alagesan): (a) Yes.

(b) and (c). The team has so far visited only the Maharashtra State: Visits to other States will be undertaken by the team on receipt of data on the pro formae prescribed for the purpose.

(d) Report will be submitted by the team on completion of the study.

दिल्ली में बिजली द्वारा दाह-संस्कार की मशीन

११३२. { श्रीम० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि बिजली द्वारा दाह संस्कार करने वाली मशीन जो दिल्ली

नगर पालिका ने दो वर्ष पूर्व एक लाख रुपये की लागत पर क्रय की थी, जंग खा रही है ;

(ख) इस मशीन को न लगाने व प्रयोग में न लाने के क्या कारण हैं ;

(ग) दिल्ली नगर निगम ने इस मशीन को लेने से क्यों इंकार कर दिया ;

(घ) इस मशीन के रखने के स्थान का किराया क्या निगम चुका रहा है, यदि नहीं, तो अभी तक कितना बकाया है ; और

(ङ) इस मशीन को यथास्थान लगाने व उसके अनुरूप काम लेने अथवा इस मशीन को बेच देने आदि प्रश्नों का कब तक निबटारा हो जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :

(क) जी नहीं, यह मशीन अच्छी हालत में है ।

(ख) यह मशीन अभी तक इसलिये नहीं लगाई जा सकी क्योंकि इसके लगाने के लिये उपयुक्त दाह संस्कार भवन नहीं बनाया गया था । अब एक उपयुक्त डिजाइन तैयार कर दिया गया है ।

(ग) यह मशीन जो नई दिल्ली नगरपालिका ने ली थी, दिल्ली नगर निगम ने उसकी लागत पर ही उनसे अप्रैल, १९६० में ले ली है ।

(घ) नई दिल्ली नगरपालिका से इस मशीन के रखने के स्थान के किराया के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है किन्तु नगर निगम को हाल ही में ४३२० रुपये के बिल मिले हैं जिन पर वे विचार कर रहे हैं ।

(ङ) दाह संस्कार के लिए भवन का एक प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है और उस पर निगम की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है । समुचित स्वीकृति के पश्चात् निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

Scheme of Reward to Efficient Workers in P. & T.

1133. **Shri S. M. Banerjee:** Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state:

(a) whether a scheme of reward to good and efficient workers in P & T has been introduced;

(b) if so, the broad features of the scheme; and

(c) when the scheme is likely to be implemented?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Communications (Shri Bhagavati): (a) to (c). No. The scheme is under consideration.

Barrage Across Jamuna at Delhi

1134. **Shri Surendra Pal Singh:** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are considering the proposal of building a second barrage across the Jamuna near the Central Power House, Rajghat, Delhi; and

(b) if so, the main details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Alagesan): (a) Yes.

(b) Details have yet to be finalised. At present model experiments are being conducted at Poona Research Institute.

Scheduled Castes and Scheduled Tribes Class IV Employees Working in Olavakkot Division

1135. **Shri P. Kunban:** Will the Minister of Railways be pleased to state how many people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been appointed in Class IV in the Olavakkot Railway Division in 1960-61 and 1961-62?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan):

	Scheduled Castes	Scheduled Tribes
1960-61	Nil	Nil
1961-62	31	Nil

Service Cooperatives under Third Plan

1136. { Shri B. K. Das;
Shri Subodh Hansda;
Shri S. C. Samanta;
Shri M. L. Dwivedi:

Will the Minister of Community Development, Panchayati Raj and Cooperation be pleased to state:

(a) the number of service co-operatives organised so far under the Third Five Year Plan;

(b) how many of them are within the Community Development Blocks; and

(c) how many of them are due to conversion from credit or other types of societies?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development, Panchayati Raj and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra): (a) and (c). Statistical statements for the co-operative year 1961-62 (ending June 1962), the first year of the Third Five Year Plan have not yet been compiled. However, according to information available, about 14,000 service cooperatives were formed during the period from 1-7-1961 to 31-12-1961; of these about 10,000 were by conversion of existing primary agricultural credit societies.

(b) Information is not readily available.

1137. { Shri A. K. Gopalan:
Shri Umanath:

Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that certain works in the Creosoting Plant in Olavakkot have been handed over to private contractors;

(b) if so, what is the reason and the details thereof;

(c) how many workers will be thrown out of work as a result thereof;

(d) whether any arrangements have been made to offer alternative employment to these workers;

(e) if so, the details thereof; and

(f) in case of alternative jobs being provided, whether the continuity of service and other privileges enjoyed by these workers will be protected?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy): (a) and (b). Yes. The works of augering of wooden sleepers and pushing of loaded trollies to the creosoting plant have temporarily been entrusted on contract basis for the following reasons:—

- (i) In the plant, as designed, the augering of sleepers has to be done by machine. However the high speed wood augers for this had to be imported and pending their receipt augering was done by departmental labour. These augers have now been received and will be installed shortly. Since in any case the labour engaged on this had to be absorbed elsewhere, the augering work was entrusted to contract labour for this short period. The contract labour

(ii) The pushing of the loaded and unloaded trollies to the Creosoting Plant was found to be cheaper through contractor's agency, than with departmental labour.

(c) 30 workers were rendered surplus as a result of entrusting the above works on contract basis.

(d) All the workers have been provided with alternative employment.

(e) Due to introduction of double shift in the plant with the improved supply position of sleepers, additional staff were required and the workers rendered surplus have been absorbed in working the second shift.

(f) Yes. The reply is in the affirmative.

Famines in Rayalaseema District, Andhra Pradesh

1138. { Shri Remeshwar Tantia:
Shri Yallamanda Reddy:

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 174 on the 25th April, 1962 and state:

(a) whether any final decision has since been taken to implement the scheme that was under preparation for the development of Rayalaseema District in Andhra Pradesh; and

(b) if so, what is the total cost involved and how much is to be borne by the Central Government?

The Deputy Minister in the Ministry of Food (Shri A. M. Thomas): (a) and (b). On the basis of the draft Plan suggested by the Government of India, the Government of Andhra Pradesh has prepared a Plan for the development of chronic drought affected areas covering 12 taluks at a cost of Rs. 807.71 lakhs.

The various schemes proposed by the State Government have been found to be generally well-conceived but need certain revision in the light of the comments of Technical Experts. The State Government has been advised accordingly.

As most of the schemes in the Plan are already being implemented as part of the Third Plan, it will only mean laying greater emphasis on some of the schemes in the drought areas. No extra financial assistance from the Centre is called for.

D.V.C. Canal

1139. **Shri Rameshwar Tantia:** Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state:

(a) whether the D.V.C. authorities have suggested to constitute a statutory corporation with the West Bengal Government as a dominant partner for dealing with the canal traffic;

(b) if so, what has been the reaction of the Central Government; and

(c) what other measures have been taken to develop the full potential of navigation in the canal?

The Minister of Shipping in the Ministry of Transport and Communications (Shri Raj Bahadur): (a) The Advisory Committee set up by the D.V.C. in the year 1958 recommended *inter alia* that the best way of running the transport organisation would be to set up a statutory authority or a separate Corporation preferably with Government of West Bengal as a dominant partner. The D.V.C. authorities have since addressed the West Bengal Government to initiate action in this behalf.

(b) The matter is under consideration of the Government of West Bengal and their reaction is awaited.

(c) The canal, which was originally scheduled to be completed by the middle of July, 1959, was damaged during the floods of 1959. Necessary repairs have been done. But there

has been silting at the tail end of Kunti Channel. For desilting, the D.V.C. authorities have placed orders for a dredger, delivery whereof is awaited. In the meantime, the D.V.C. authorities have requested the Government of West Bengal for a loan of one of their dredgers for the purpose.

भाखड़ा बांध परियोजना

११४०. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा बांध के पूरा होने में अभी कितना और समय लगेगा, ;

(ख) क्या बांध के पूरा होने पर ही जलाशय भरा जायेगा ; और

(ग) भाखड़ा के दूसरे सिरे पर बिजलीघर का निर्माण कब पूरा होगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अल्लगशन) : (क) बांध के शिखर पर के कुछ कार्यों नामशः उमड़मार्ग पुल, (स्पिलवे ब्रिज), 'पैरापेट्स' और रेडियल गेट्स' को छोड़ कर मुख्य बांध और आनुषंगिक कार्य पूर्ण हो गये हैं। इन बाकी रह गये कार्यों को हाथ में लिया हुआ है और आशा है कि ये १९६२ के खत्म होने से पहले ही पूर्ण हो जायेंगे।

(ख) भाखड़ा जलाशय में पहले से ही १९५८-५९ से जल का कुछ हिस्सा इक्टा किया जा रहा है। जलाशय का स्तर हर वर्ष ऊपर उठाया जा रहा है और आशा है कि जलाशय १९६४-६५ में इसकी अधिकतम अभिकल्पित ऊंचाई तक भर दिया जाएगा।

(ग) आशा है कि भाखड़ा दक्षिण तट बिजलीघर, अप्रैल, १९६६ तक पूर्ण हो जाएगा।

पाकिस्तान के साथ रेल सम्बन्ध

११४१. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में होकर पाकिस्तान के दोनों भागों का सम्बन्ध जोड़ने वाली रेल श्रृंखला की बातचीत सर्वथा समाप्त हो गयी है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसमें निर्णय लेने में क्यों देर हो रही है ;

(ग) भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों की कटुता को ध्यान में रखते हुए भी क्या सरकार बातचीत चालू रखना चाहती है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक होने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (घ). १६ नवम्बर से १८ नवम्बर १९६० तक रावलपिण्डी में जो बैठक हुई थी, उसमें भारत और पाकिस्तान के शिष्ट-मण्डल जिन मुद्दों पर एक राय से भारत सरकार ने उनका अनुसमर्थन (ratification) अभी नहीं किया है और इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार से आगे कोई बातचीत नहीं चल रही है। उचित समय आने पर सभी सम्बन्धित बातों को ध्यान में रखकर फ़ैसला किया जायेगा।

F.A.O. Expert

1142. **Shri Shree Narayan Das:** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state the precise nature of work assigned to U.N. Food and Agriculture Organisation expert Mr. A. Welle, invited by Government?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas): The work assigned to Mr. Welle is of an advisory nature and covers (i) dairy surveys, (ii) determination of economic units for hand-

ling liquid milk and manufacturing dairy products and (iii) examination of the economic aspects of the production, handling and marketing of milk and milk products.

Telephone Exchange at Trichur

1143 { **Shri Warior:**
Shri Vasudevan Nair:

Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state:

(a) whether the construction of the building to house the automatic telephone exchange at Trichur has been started; and

(b) if not, the reason for the delay?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Communications (Shri Bhagavati): (a) No.

(b) Transfer of land from the State Government is awaited.

Demographic Cells

1144. { **Shri Warior:**
Shri Vasudevan Nair:
Shri M. K. Kumaran:

Will the Minister of Health be pleased to state:

(a) whether Government have taken any action to see that State Governments and Municipal Corporations set up democratic cells attached to their respective health departments; and

(b) if so, the results thereof?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) The Government of India have offered 50 per cent. Central subsidy to the State Governments for appointment of one Computer in each primary health centre and one Investigator and one Computer in the office of the District Family Planning Officers. A proposal to establish demographic cells at the State Headquarters is under consideration. The scheme does not envisage the grant of assistance to Municipal Corporations for the purpose.

(b) Proposals are awaited from the State Governments.

D.T.U. Bus Service to Meerut

1145. Shri Bishanchander Seth: Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state:

(a) whether the Delhi Transport Undertaking has evolved a scheme for running its service upto Meerut in U.P.;

(b) whether the Government of Uttar Pradesh have not granted licenses to D.T.U. to run its services upto Meerut while the buses of U.P. Roadways are permitted to run upto Delhi;

(c) whether the D.T.U. has requested the Central Government to take up the matter with the Government of U.P.; and

(d) what has been the reaction of the Government of U.P. thereto?

The Minister of Shipping in the Ministry of Transport and Communications (Shri Raj Bahadur): (a) to (d). The U.P. Government buses are plying on the various routes converging on Delhi. Delhi Transport Undertaking of the Delhi Municipal Corporation is not, however, operating on any of these routes at present.

2. In 1949, the Government of Uttar Pradesh and the Delhi Administration entered into a reciprocal agreement, according to which the U.P. Government would have the monopoly of bus operation on these routes till the Delhi Administration was in a position to run its services.

3. In 1960 the Delhi Transport Undertaking obtained ten permits from the State Transport Authority, Delhi for the Delhi-Meerut route. The U.P. Government did not countersign these permits on the ground that the share of the Delhi Administration could not be utilised by the Delhi Transport Undertaking as buses of this Undertaking could not be deemed to be the buses of the Delhi Administration.

4. On a request from the Delhi Transport Undertaking, the Central Government took up the matter with

the U.P. Government, but no settlement has so far been reached. The matter has been referred to the Interstate Transport Commission with whom it is now pending.

5. Recently, as a result of the efforts of the Commission, the Transport Authorities in U.P. agreed to allow the D.T.U. to operate between Delhi and Ghaziabad. They propose to increase the number of permits on the Delhi-Ghaziabad route from 20 to 30 and have intimated that they will have no objection to countersign these additional ten permits if the State Transport Authority Delhi issue them to the Delhi Transport Undertaking or any private transport operators in Delhi. This proposal is under examination in the Delhi Administration.

Railway Line connecting Cement Factory in Vijayanagaram Taluk (Andhra Pradesh).

1146. Shri Yallamanda Reddy: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Railways have not yet provided a necessary railway line connecting the main line for the proposed cement factory in Vijayanagaram Taluk, in Visakhapatnam District, Andhra Pradesh; and

(b) when the proposals were made?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy):

(a) No concrete proposal for a rail connection from the existing main line for the proposed cement factory in Vijayanagaram Taluk in Visakhapatnam District, Andhra Pradesh, has yet been received.

(b) Does not arise.

Panchayat Committee

1147. Shri Dasaratha Deb: Will the Minister of Community Development, Panchayati Raj and Cooperation be pleased to state:

(a) whether there is any provision for the reservation of seats for the Scheduled Castes and Scheduled

Tribes in the Panchayat Committees in West Bengal; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development, Panchayati Raj and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra): (a) No such provision has been made in the West Bengal Panchayat Act, 1956.

(b) Under Section 29 of the Act, the right to constitute any committee of the Anchal Panchayat has been vested in the main body itself. The composition of each such committee is also to be decided by the Anchal Panchayat.

Tribal Panchayats

1148. Shri Dasaratha Deb: Will the Minister of Community Development, Panchayati Raj and Cooperation be pleased to state:

(a) whether the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has suggested in his Tenth Report to recognise the traditional tribal Panchayats as associate bodies for different purposes according to local conditions;

(b) if so, what step Government propose to take in Tripura in this respect; and

(c) when Tripura Kshatrya Mandal Committees were abolished and what were the reasons?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development, Panchayati Raj and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra): (a) Yes Sir. According to the Commissioner, this is one of the directions in which provisions will have to be made to safeguard the interests of Scheduled Tribes and Scheduled Castes, under Panchayati Raj.

(b) In Tripura, Panchayats are being established in six blocks during 1962-63 and the entire territory will be covered by Panchayats by April, 1965. This suggestion will be considered at the appropriate time after Panchayats have started functioning in Tripura.

1531 (Ai) LSD—4.

(c) The information is being collected.

Transport Development Council

1149. Shri Dasaratha Deb: Will the Minister of Transport and Communications be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 567 on the 25th November, 1961 and state:

(a) to what extent the suggestions made by the Transport Advisory Council held in October, 1961 have so far been implemented; and

(b) whether any steps have been taken to give tax relief to transport operators?

The Minister of Shipping in the Ministry of Transport and Communications (Shri Raj Bahadur): (a) A statement giving the information required is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-343/62.]

(b) One of the recommendations made by the Transport Development Council was that in order to encourage motor transport in rural areas, some tax concession might be allowed to operators serving such areas. The extent and the form of relief, which depended on local conditions, were to be examined by the State Governments. The matter has been taken up with them.

Haldia Port

1150. Shri Dasaratha Deb: Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state:

(a) whether the scheme for the development of Haldia as satellite deep draft port has been finalised;

(b) if so, the progress made to set up the Port; and

(c) when the actual work is likely to be started?

The Minister of Shipping in the Ministry of Transport and Communications (Shri Raj Bahadur): (a) A scheme for the development of a new dock system at Haldia, which will be complementary to the port facilities at

Calcutta, has been prepared by the Calcutta Port Commissioners.

(b) A Project Report has been prepared. A Master Plan for the development of the Port has also been prepared. The detailed planning of the Project is at present being attended to by the Port Commissioners. Sanction has been accorded by Government of India to the acquisition of 9.373 square miles of land required for the project and steps are being taken by the Commissioners through the West Bengal Government to acquire the land in phases.

(c) According to a tentative time-schedule drawn up by the Commissioners, preliminary works are likely to commence in March 1963.

Family Planning

1151. { Dr. L. M. Singhvi:
Shri Hem Barua

Will the Minister of Health be pleased to state:

(a) the extent to which the official efforts in the matter of family planning have been able to check the rate of increase in population in our country; and

(b) the measures proposed to be taken to check increase in the population during the Third Five Year Plan period?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) It is too early to make a considered assessment of the effect of the family planning programme to check the rate of increase in population of the country.

(b) The following are some of the important schemes approved for implementation to check increase in the population during the Third Five Year Plan period:—

- (i) Pilot scheme for appointment of male and female depot holders on an honorarium of Rs. 7/- per month for distribution of contraceptives in

selected villages. The State Governments have been requested to consider the desirability of extending the pilot scheme in the States.

- (ii) Pilot scheme for training and appointment of Dais on an honorarium of Rs. 10/- per month for motivating people and distribution of contraceptives to them in their respective localities has been approved. Dais are expected to play a notable part in popularising family planning practices among the people in their areas and the cooperation of the dais in extending the programme particularly in rural areas is considered very vital.
- (iii) Establishment of family planning clinics in each primary health centre and its three sub-centres on an approved pattern of financial assistance.
- (iv) Establishment of urban family planning clinics on an approved pattern of financial assistance which has been liberalised.
- (v) Provision of mobile family planning clinic in each district in the States on an approved pattern of assistance.
- (vi) Financial assistance for District Family Planning Sub-committees at the rate of Rs. 2,000/- per annum per committee and Rs. 500/- per annum for each Family Planning Sub-committees at tehsil/taluk level has been offered to all State Governments to meet expenditure on clerical assistance etc. in connection with the functions of each Sub-committee.
- (vii) 100 per cent financial assistance has been offered to the State Governments for the provision of facilities for

sterilization operations in the district hospitals and also in the taluk/tehsil hospitals in the States subject to a maximum of Rs. 10,500/- per annum in each case and for training of persons in medical teaching institutions in the technique of sterilization operations and mobile surgical units. Financial assistance has also been offered to the States to meet expenditure on transport of the persons undergoing sterilization operations, where transport facilities for them are not available at the primary health centres.

(viii) Family Planning exhibition sets have been procured and supplied to State Governments for conducting family planning exhibitions in districts in the States.

(ix) A number of posters and pamphlets have been printed and films have been produced.

(x) Honorary Family Planning Education Leaders have been appointed in the States. proposals for such appointments in the remaining districts are under consideration.

(xi) 50 per cent. Central subsidy has also been offered to the States for the appointment of a District Family Planning Officer in each district.

(xii) Contraceptives are distributed free and at subsidised rates. In rural areas they are distributed free irrespective of income.

(xiii) 100 per cent. financial assistance is offered to Local Bodies and Voluntary Organisations for family planning services.

(xiv) Research in demographic, motivational, and biological fields is being carried out.

National Highways in Kerala

1152. **Shri P. Kunhan:** Will the Minister of Transport and Communications be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 659 on the 11th May, 1962 regarding National Highways in Kerala and state:

(a) whether items Nos. 35 to 44 mentioned in the statement in respect of National Highway Nos. 47 and 47-A have been included in the Third Five Year Plan; and

(b) if so, whether the works have been started?

The Minister of Shipping in the Ministry of Transport and Communications (Shri Raj Bahadur): (a) Only item No. 37 has been included in the Third Five Year Plan. Efforts are also being made to include Item No. 44 in the Third Five Year Plan.

(b) No, Sir.

Road Transport Undertakings

1153. **Shri P. Kunhan:** Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state:

(a) the amount provided State-wise for expansion programme of nationalised road transport undertakings in the first two years of the Third Plan and also under the Railway Plan;

(b) the amount spent, State-wise out of this allocation;

(c) whether any difficulties are being faced in this matter; and

(d) if so, what are they and what steps are being taken by Government to expedite the matter?

The Minister of Shipping in the Ministry of Transport and Communications (Shri Raj Bahadur): (a) to

(d). The information required is being collected from the States/Union Territories and will be laid on the Table of the House as soon as it becomes available.

Preservation of Fish

Shri A. K. Gopalan:

1154. { **Shri Umanath:**
 { **Shri P. Kumhan:**

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether the Central Fisheries Technological Institute has taken any measures for research to preserve the huge quantities of sardine and other varieties of fish catch in the coastal areas of Kerala and Minicoy Islands; and

(b) if so, what are the steps?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas): (a) Yes.

(b) The Central Institute of Fisheries Technology, Ernakulam, has been carrying out investigations to preserve sardine and other varieties of fish caught in the coastal areas of Kerala and the Minicoy Islands. Some of the important items of work are the evolution of a hot air tunnel dryer, preparation of semi-dried prawns, preservation of fish with chemicals like propionic acid, improved salt curing, experiments on canning, freezing etc., preservation of sardine and mackerelin oil and smoking of mackerel and sardine. Preparation of fish sauce, fish oil, etc., also form part of the programme.

कृषि योग्य परती भूमि

११५५. { श्री भक्त वर्शन :
 { श्री राम सेवक यादव :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २५ अप्रैल, १९६२ के अतारंकित प्रश्न संख्या १६३ के

उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :
 कि

(क) (क) देश भर में परती जमीन का पता लगाने के लिए नियुक्त विशेषज्ञ समिति के कार्य में और क्या प्रगति हुई है ;

(ख) उस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई योजना का क्या स्वरूप है ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए केन्द्र द्वारा क्या सहायता दी जा रही है अथवा देने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) समिति ने महाराष्ट्र के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उड़ीसा के सम्बन्ध में रिपोर्ट का मसौदा राज्य सरकार के सम्बन्धित अफसरों को भेज दिया गया है और उन से कहा गया है कि वह इसको अन्तिम रूप देने के लिए एक बैठक का आयोजन करें। इसी प्रकार गुजरात सम्बन्धी रिपोर्ट के मसौदे को भी भेजा जा रहा है।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति के बारे में अभी तक अपने प्रस्ताव नहीं भेजे हैं।

(ग) जहाँ समिति द्वारा निशान लगाई गई भूमि को विशेषकर भूमिहीन मजदूरों के पुनर्वास के लिये सुधारा जाता है, केन्द्रीय सरकार सुधार पर खर्च होने वाले 'अनुदान' और 'ऋण' के आधे खर्च को देगी परन्तु यह इस शर्त पर कि अलाटशुदा भूमि पर होने वाला खर्च १५० रुपये प्रति एकड़ से अधिक न हो।

**अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना
मूल्यांकन समिति की सिफारिशें**

११५६. { श्री भक्त दर्शन :
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या स्वास्थ्य मंत्री २५ अप्रैल, १९६२ के अतारंकित प्रश्न संख्या १५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना अनुसंधान समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए इस बीच और क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :
एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या १२]

**अतिरिक्त विभागीय डाकघर,
अफजलगढ़**

११५७. श्री भक्त दर्शन : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ४ जून, १९६२ के अतारंकित प्रश्न संख्या २४७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफजलगढ़ (जिला बिजनौर) स्थित अतिरिक्त विभागीय डाकघर को विभागीय उप-डाकघर में परिवर्तित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका दर्जा कब से बढ़ाया गया है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भगवती) : (क) जो हां ।

(ख) २-७-१९६२

Railway Zone for Andhra Pradesh

1158. Shri P. Venkatasubbaiah: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether the Chief Minister of Andhra Pradesh has represented for creation of a separate Railway zone for Andhra Pradesh during his recent visit to Vijayawada and Hyderabad on 7th of July 1962; and

(b) if so, whether Government propose to reconsider the matter in view of the urgency and necessity of creation of such a zone?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shah Nawaz Khan):

(a) No. The Chief Minister of Andhra Pradesh made no such representation, but the Andhra Minister for Excise and Prohibition, who presided on the occasion of the inauguration of the Broad Gauge line between Vijayawada and Masulipatam at Vijayawada on 7th July 1962, made a request in this connection in his presidential address amongst other observations.

(b) The question of "reconsideration" of the matter does not arise, as the Government have taken no static view in regard to this question and have always kept an open mind as regards justification for new Railway Zones or any other re-organisation—not on regional considerations or with reference to regional limits but with reference to operational and administrative requirements, service to railway users, etc.

पंचायती न्यायालयों की कार्यविधि

११५९. श्री भक्त दर्शन : क्या सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री २८ मई, १९६२ के अतारंकित प्रश्न संख्या २०८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर की पंचायती न्यायालयों की कार्यविधि आदि के बारे में नियुक्त अध्ययन दल ने अपनी जो रिपोर्ट कुछ समय पहले प्रस्तुत की थी उसकी मूल्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ख) उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इयासधर मिश्र) : (क) न्याय पंचायत अध्ययन दल की रिपोर्ट १५ जून, १९६२ को सभा-पटल पर रख दी गई है; रिपोर्ट की प्रतियां संसद पुस्तकालय में भी उपलब्ध हैं। अध्ययन दल के मुख्य निष्कर्ष रिपोर्ट के पृष्ठ १२४ से १२६ पर दिये गये हैं।

(ख) अध्ययन दल की प्रमुख सिफारिशों पर दिल्ली में हाल ही में हुए सामुदायिक विकास के वार्षिक सम्मेलन तथा राज्यों के सामुदायिक विकास और पंचायती राज मन्त्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया है। इन सम्मेलनों ने सामान्यतः अध्ययन दल की सिफारिशों से सहमत होते हुए कुछेक सुझाव दिये हैं। रिपोर्ट भारत सरकार के विचाराधीन है।

G. B. Hospital and V. M. Hospital, Agartala

1160. **Shri Dasaratha Deb:** Will the Minister of Health be pleased to state:

(a) the total number of Ambulance cars and other Motor Vehicles put at the disposal of the Medical authorities of Gobind Ballab Pant Hospital and V. M. Hospital, Agartala, Tripura;

(b) whether they are adequate; and

(c) if not, steps taken to increase the number of such vehicles immediately?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayyar): (a) Two Ambulance Vans and one Jeep.

(b) No.

(c) The Government of India have accorded sanction to the purchase of two Ambulance Vans and the Tripura Administration are taking necessary action to purchase the Vans.

Scholarships to Railway Employees' Children

1161. **Shri G. Mohanty:** Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether Railway Board has any scheme for granting scholarships to children of their employees of any branch;

(b) if so, number of scholarships granted during 1961-62 and 1962-63; and

(c) whether Government will place the detailed scheme on the Table?

The Deputy Minister in the Ministry of Railway (Shri Shahnawaz Khan): (a) and (c). Yes Details of the scheme are given in the statement laid on the Table of the House. [See Appendix II, annexure No. 13.]

(b) 1961-62	999
1962-63	1000
	(approximately).

वन महोत्सव

११६२. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या साख तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वन महोत्सव का कार्यक्रम जब से आरम्भ किया गया है तब से कितने वृक्षों का रोपण हुआ और उनमें से कितने आज विद्यमान हैं ?

साख तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : १९५० से १९५९ तक की अवधि में लगाये गये और उनमें से जीवित रहने वाले वृक्षों की संख्या निम्न प्रकार है : -

लगाये गये वृक्ष ३८,१५,४६,८३१

जीवित रहने वाले वृक्ष १९,२५,८९,५३१
इसके बाद के वर्षों के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

Retired Railwaymen in Tiruchi Division

1163. { **Shri A. K. Gopalan:**
Shri A. V. Raghavan:

Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that re-

tired railwaymen in Tiruchi Division are being paid their final settlement of dues on the day following the date of their retirement;

(b) the number of Railwaymen who have retired since this scheme had been initiated on Tiruchi Division and the total amount paid to them; and

(c) whether there is any proposal before Government to extend the scheme to other divisions of the Indian Railways?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan): (a) Yes, in case of employees other than commercial staff and staff handling stores who have opted for State Railway Provident Fund.

(b) Since 1st December, 1961 when the scheme was initiated, 143 men retired from service and a total amount of Rs. 5,97,136, was paid to them.

(c) Instructions already exist that, as far as possible, payment of Provident Fund dues should be made within 10 days of retirement. Railways do try to reduce this limit wherever possible.

Jammu and Kashmir Link by Micro-wave.

1164. Shri P. C. Borooah: Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to link Kashmir valley with Jammu by Micro-wave system; and

(b) if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Communications (Shri Bhagavati): (a) Yes.

(b) Srinagar, Jammu and Udhampur will be linked by multi-channel carrier telephone systems operating on microwave radio relay links.

Bhutan Postal Stamp

1165. Shri Kaghunath Singh: Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state whether in view of the fact that Bhutan is not a member of the Universal Postal Union any agreement between the Postal Administration of India will be signed specially when Bhutan is issuing her own postal stamps designed at U.S.A. and printed in U.K.?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Communications (Shri Bhagavati): The question of entering into a bilateral agreement with Bhutan is under consideration.

Nalagarh Committee

1166. { Shri D. C. Sharma:
Shri Inder J. Malhotra:
Shri Kolla Venkaiah:

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) the up-to-date progress made regarding the implementation of the Nalagarh Committee recommendations; and

(b) the progress made so far in taking a decision with regard to the creation of the All India Agricultural Service?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh): (a) A statement giving the required information is laid on the Table of the House. [See Appendix II, annexure No. 14.]

(b) The question of creation of an All India Agricultural Service is under examination.

Production and Distribution of Fertilizers

1167. Shri D. C. Sharma: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any policy in respect of pro-

duction and distribution of fertilizers; and

(b) to what extent this production and distribution has been allowed to private sector during the last three years and on what terms and conditions?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh): (a) and (b).

Production: Under the Industrial Policy Resolution of 1956, the development of fertilisers industry comes under Schedule B, which comprises a list of industries in which the State will take the initiative in establishing new undertakings, but private enterprise will also be expected to supplement the effort of the State. The policy enunciated therein continues to be followed.

The existing and licensed|approved capacity for nitrogen in the private sector is as under:—

(i) Existing	10,000 tons	} Out of a total of 1259,800 tons
(ii) Licensed/ approved	526,500 tons	
TOTAL	536,500 tons	

Out of the total existing capacity of about 99,400 tons of P205, 83,400 tons is at present in the private sector.

Distribution: In regard to distribution, while the Co-operative Societies (which is also private sector) are encouraged to distribute fertilisers, in most States, the private sector manufacturers also make their own arrangements to market their products e.g., single super-phosphate and ammonium chloride.

Mangalore and Tuticorin Ports

1168. Shri D. C. Sharma: Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state:

(a) the latest position regarding development of Mangalore and Tuticorin ports; and

(b) the details thereof?

The Minister of Shipping in the Ministry of Transport and Communications (Shri Raj Bahadur): (a) and (b). At Mangalore, the experiments and investigations to decide whether the Port is to be sited to the north or the South of the Netravati River mouth, in order to exclude the Netravati silt from entering the harbour, have been completed. These experiments and investigations have revealed that the Port should be sited north of the Netravati mouth.

Further detailed investigations, borings and surveys are being conducted by the Field Division, recently established by the Government of India, for finalising the lay-out of the Port. Thereafter, the detailed estimates and designs will be prepared.

As regards Tuticorin, the detailed investigations for determining the lay out of the Port and for the preparation of designs and estimates are being carried out by the Field Division, recently set up by the Government of India. Twenty borings in the sea upto a level of 40 ft. below water have been completed and the results of these borings are being examined in detail in order to finalise the lay out. Therefore, the drawing up of detailed designs and estimates will be taken up.

Railway Line from Tsundur to Guntur

1169. Shri Kolla Venkaiah: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether railway line from Tsundur to Guntur (Southern Railway) which is to serve as a diversionary line has been completed;

(b) the trains that will be diverted from Tsundur to Guntur;

(c) whether the present railway station of Guntur will serve this line also; and

(d) what is the total cost of the scheme for diversion?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy): (a) Yes.

(b) Some of the through goods trains from Tsundur to Vijayawada and vice versa will be diverted via Vejedla.

(c) No. A bye-pass line has been provided near Guntur connecting Vejedla-Guntur line with Guntur-Tadepalle B.G. line without touching Guntur station and the through goods trains will run by this by-pass line.

(d) About Rs. 59.12 lakhs.

Teleprinter

1170. Shri N. Sreekantan Nair: Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the teleprinters allotted to a defunct news agency Indian News Service—for the particular use for news service are now being used by Chain news-paper which controlled the majority of the shares; and

(b) whether Government have permitted the use of the teleprinter by Chain newspaper?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Communications (Shri Bhagavati): (a) No.

(b) Does not arise.

Education Allowance to Children of Railway Employees

1171. Shri P. Kuman: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have issued orders sanctioning education allowance for the children of all Central Government employees;

(b) if so, whether it is a fact that Railway employees have not been sanctioned this allowance; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan): (a) to (c). Under the rules in force on the Railway side, educational assistance is given to Railway em-

ployees who are compelled to send their children away from their headquarters for the purpose of education. As recommended by the Pay Commission the Ministry of Finance have formulated a scheme regarding grant of educational allowance for the children of Central Government employees on the civil side based on the scheme on the Railway side. The two schemes are not identical and while in some respects the Railway rules in this regard are more liberal than the rules framed by the Ministry of Finance, in some other respects the Ministry of Finance rules are more liberal. The question as to what extent the Ministry of Finance rules should be adopted on the Railway side is under examination.

Post Office in Parliament Street

1172. Maharajkumar Vijaya Ananda: Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state:

(a) whether a new post office has been opened in Parliament Street, New Delhi in June, 1962;

(b) whether the building was meant for New Delhi G.P.O.; and

(c) if so, the reasons for housing this Post Office?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Communications (Shri Bhagavati): (a) Yes.

(b) It was contemplated at the planning stage to shift the General Post Office in this building.

(c) Due to paucity of accommodation a new and smaller Post Office was opened in the building.

Utilisation of Oil Survey Wells for Drinking Water Supply

1173. Shri Ram Ratan Gupta: Will the Minister of Health be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to utilise unyielding oil survey wells for drinking water supply in the country; and

(b) if so, whether the proposal has been accepted by the Ministry of Mines and Fuel?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) The idea to utilise unyielding oil survey wells for purposes of supply of drinking water is under consideration. No specific proposal in this connection has yet been worked out and referred to the Ministry of Mines & Fuel. In informal talks with Minister for Health the Minister of Mines & Fuel was sympathetic to this idea.

(b) Does not arise.

Free Railway Passes for P. & T. Staff

1174. Shri Yashpal Singh: Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state:

(a) which categories of the Officers of Posts and Telegraphs Department are issued free railway passes (Card Passes etc.);

(b) what are the checks to see that these officers do not misuse these passes for private purposes;

(c) whether any form like the one filled in by Members of Parliament on the completion of their journeys is also required to be filled in by these officers/staff at the destination station to check the malafide use of such card passes; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Communications (Shri Bhagavati): (a) A list is placed on the Table of the House. [See appendix II, annexure No. 15].

(b) Misuse of passes renders an official liable for disciplinary action. They are kept in the custody of responsible officers in the larger offices and are subject to check by the Railway Staff.

(c) No.

(d) The form required to be filled in by Members of Parliament is for the purpose of raising necessary debit by the Railways against the LokRajya

Sabha Secretariat. Cost of journeys undertaken by officers of the Posts and Telegraphs Department by using duty card passes is not to be paid to the Railways and consequently such forms are not required to be filled in by the personnel of the Posts and Telegraphs Departments.

Railway Line from Ongole to Hyderabad

1175. Shri M. N. Swamy: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether the Government of Andhra Pradesh proposed the construction of a new Railway line from Ongole to Hyderabad during the Third Plan period; and

(b) if so, the reaction of the Central Government?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy): (a) Yes.

(b) The proposal is not included in the Railway's programme of construction of new lines for the Third Five Year Plan.

Deficiency in Foodgrains

1176. Dr. K. L. Rao: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) the deficiency in foodgrains during the last three years in respect of (i) Rice and (ii) Wheat;

(b) what are the costs involved in obtaining these from outside in respect of following (i) price paid (ii) shipping costs (iii) miscellaneous expenditure;

(c) whether there are projects undertaken already, which if completed earlier, can make good the deficiencies in respect of (i) Rice and (ii) Wheat; and

(d) if so, whether Government intend to accelerate these projects on priority basis to stop further imports?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas): (a) It is difficult to estimate precisely the consumption requirements of foodgrains in India where a large number of consumers are producers themselves. During the last three financial years 1959-60, 1960-61 and 1961-62 the nett distribution of imported rice and wheat from Central stocks, however, was approximately as follows:—

(in million metric tons)

Grain	Quantity
Rice	1.0
Wheat	9.5

This may be taken to be a rough measure of the deficiency of foodgrains in the country during the last 3 years and it would work out to an average of about 3,30,000 tons of rice and 3.2 million tons of wheat.

(b) The average economic costs involved in obtaining rice and wheat from outside during the financial years 1959-60, 1960-61 and 1961-62 were as follows:—

(All rates in Rupees per metric ton)

Commodity	Price of grain. F.O.B. supplying country	Sea Freight	Incidentals in India	Total
Rice	472.04	47.29	49.83	569.16
Wheat.	285.37	40.80	61.27	387.44

(c) and (d). All possible steps are being taken to increase the production of foodgrains in the country. The various schemes under the Third Five Year Plan are being executed as expeditiously as possible and it is expected that if the target of production of 100 million tons for the Third Five Year Plan period is achieved, the country will become self-sufficient in foodgrains.

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Communications (Shri Bhagavati): (a) and (b). Two major accidents involving IAC Indian Airlines Corporation aircraft took place during the current year. A statement giving details thereof is placed on the Table of the House. [See Appendix II, annexure No. 16].

Air Accidents

1177. { Shri Inder J. Malhotra:
Shri Sarkar Murmu:
Shri P. C. Borooah:

Will the Minister of **Transport and Communications** be pleased to state:

(a) the nature and number of accidents met by the IAC planes flying on various routes in the country during 1962 so far; and

(b) the type of inquiries instituted and their findings?

बम्बई में बूचड़खाना

११७८. श्री तनसिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में एक नया बूचखान (देवनार बूचड़खाना) खोलने की योजना बनाई गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसमें प्रतिदिन ६०० भेड़ बकरी, ३०० गाय बैल और १०० सूअर काटने की क्षमता होगी ;

(ग) इस योजना पर कितना रुपया खर्च किया जायेगा ;

(घ) केन्द्रीय सरकार योजना में कितनी धन-राशि और किस शर्त पर खर्च करेगी ; और

(ङ) क्या सरकार को अब तक किसी से इस योजना के विरुद्ध विरोध पत्र भी प्राप्त हुए हैं ?

लाख तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्री ० म० थॉमस): (क) बान्द्रा में स्थित वर्तमान बूचड़खाना जिसे बने हुए १५ वर्ष हो गए हैं, अपनी उपयोगिता के समय से भी अधिक समय तक कार्य कर चुका है। शहर का विस्तार होने के कारण अब वह रिहायशी क्षेत्र के मध्य में आ गया है जिससे वहां पर अस्वास्थ्यकर स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसमें पदार्थों की पूर्ण उपयोगिता के लिये पर्याप्त प्रबन्ध नहीं हैं। चूंकि बूचड़खाना बर्ड-प्रूफ (Bird Proof) नहीं है, उस क्षेत्र के गिद्ध समीप के संटाकूज स्थापर्ट पर उतरने वाले बड़े विमानों के लिए भी भय उत्पन्न करते हैं। बम्बई नगर निगम ने शहर के मध्य से १८ मील दूर देवनार में एक नए स्थान पर इस वर्तमान बूचड़खाने के पुनर्निर्माण के लिए एक योजना बनाई है? देवनार के बूचड़खाने के चालू हो जाने पर निगम महा-बम्बई के समस्त बूचड़खानों को बन्द कर देना चाहती है। देवनार के प्रस्तावित बूचड़खाने में ३०० पशु, ६१६० भेड़ तथा बकरी और १०० सूअर प्रतिदिन काटने की क्षमता होगी। यहां यह भी बताना उचित होगा कि आजकल अकेले बान्द्रा बूचड़खाने में लगभग २५० पशु और ३,५०० भेड़ तथा बकरी पहले से ही काटे जा रहे हैं।

(ग) इस बूचड़खाने के निर्माण पर खर्च आने वाली कुछ अनुमानित राशि १४६ लाख रुपये है। फिर भी, इस प्रयोजना के लिए राज्य सरकार ने अपनी तृतीय पंच वर्षीय योजना में १२३ लाख रुपये का उपबन्ध किया है।

(घ) इस योजना के लिए केन्द्रीय सरकार सहायता के रूप में शत प्रतिशत ऋण देगी।

(ङ) जी हां। इस और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया गया है।

Himachal Resin and Turpentine Factory

1179. Shri Tan Singh: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether a fire broke out in the Himachal Resin and Turpentine Factory at Nahar on the 29th December, 1961;

(b) whether the main distillery and entire Resin in stock etc. had been burnt down causing a loss of Rs. 7 lacs;

(c) whether an enquiry was conducted on the cause of fire; and

(d) if so, the result of the enquiry?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas): (a) Yes.

(b) Yes, except for the record office building, boilers, some portion of resin and turpentine and other buildings and sheds. The loss has been estimated at Rs. 5,27,000.

(c) The Police was asked to make an investigation.

(d) The result of the investigation is awaited.

Agricultural Production Board

1180. Shri P. K. Deo: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) the work done by the Agricultural Production Board set up by Government a few years back;

(b) whether Government propose to continue the Board; and

(c) if so, what measures Government propose to take to make the Board effective?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh): (a) The Inter-Ministerial Agriculture Production Board, which was constituted by the Department of Agriculture in 1959, has been examining the final result of research having bearing on agricultural production and making recommendations for the propagation and demonstration of such results by State Governments with a view to their utilisation for improving agriculture. It has also been considering fresh problems having bearing on agricultural production for research and reviewing the progress of work thereon from time to time.

(b) Yes.

(c) The Board which is an Advisory Body, has been effectively fulfilling the objectives for which it was constituted.

Research on Cotton Oilseeds and Millets

1181. Shri P. K. Deo: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Control at the regional research centres set up by the Central Government in various States for research on Cotton, Oilseeds and Millets is not effective;

(b) if so, whether it is the intention of Government to transfer the stations to the State Governments concerned; and

(c) if not, when Government propose to set up a proper machinery at the Centre to supervise the working of the scheme?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh): (a) to (c). These centres are in charge of Regional Officers who work under the adminis-

trative supervision of the Directors of Agriculture of the States in which the centres are located. Their technical programmes are approved and sanctioned by the Indian Central Cotton and Oilseeds Committee and by the Indian Council of Agricultural Research. The centres are frequently inspected and technically supervised by the Additional Agriculture Commissioner of the Indian Council of Agricultural Research, who receives from them periodical progress reports. These existing arrangements are working satisfactorily and it is not proposed to make any change in them.

Ganganagar-Hindumal-Kote Railway Line

1182. Shri Karnj Singhji: Will the Minister of Railways be pleased to state whether survey report and estimates to lay broad gauge line from Ganganagar to Hindumal-Kote have been finalised?

The Deputy Minister in the Ministry Railways (Shri S. V. Ramaswamy): Yes.

Unified Body of Traffic Control

1183. Shri P. C. Borooah: Will the Minister of Health be pleased to state:

(a) whether constitution of a unified body for traffic control in Delhi has been recommended under the Master Plan;

(b) if so, what is Government's decision in the matter; and

(c) what action has been taken to implement this decision?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) The Master Plan for Delhi has recommended that to deal with the traffic problems of Urban Delhi, which requires continuous attention to a large number of problems, a Traffic Department be set up under a trained traffic engineer and the enforcement of traffic control may continue to be the responsibility of the police, with proper liaison between the two.

(b) The Master Plan for Delhi in which the recommendation referred to in reply to part (a) above has been made, has been approved by the Central Government.

(c) Necessary action to implement the recommendation will be taken in due course.

Kufri as Winter Sports Centre

1184. Shri Heda: Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state:

(a) whether 'Kufri' in Himachal Pradesh has been selected for the winter sports;

(b) what other places are being considered in this regard;

(c) the details of the scheme; and

(d) whether the needs of foreign tourists have also been taken into consideration?

The Minister of Shipping in the Ministry of Transport and Communications (Shri Raj Bahadur): (a) to (d). The Central Government on expert advice have dropped the proposal for establishing a winter sports centre at Kufri.

The Third Five Year Plan for development of Tourism includes a scheme for development of Winter Sports at Gulmarg (Kashmir) at an estimated cost of Rs. 20.00 lakhs. The expenditure is to be incurred directly by the Central Government. The development of winter sports also envisages installation of ropeways for taking up sports enthusiasts from Gulmarg to Alpathar. The scheme is being co-ordinated with the Department of Atomic Energy who have proposals to instal a ropeway from Gudmarg to Apherwat to carry their scientists and equipment. That Department had the area surveyed initially by a party of Czech Engineers who had suggested a certain alignment for the ropeway. At the instance of the Department of Tourism, a Winter Sports expert from Austria visited the area in December

1960 and he suggested certain changes in the alignment of the ropeway. For making Gulmarg accessible during winter he recommended construction of an all-weather motorable road from Tangmarg to Gulmarg. In case it was not practicable to keep the road between Tangmarg and Gulmarg open during the winter months due to heavy snow, he suggested the installation of a ropeway between Tangmarg and Gulmarg also. The Department of Atomic Energy obtained the services of a French Consulting Engineer in September—October, 1961 to advise on the various technical aspects of the scheme. The Central P.W.D. are now making a physical survey of all the suggestions with a view to preparing an estimate of costs of the whole sheme. Hence the details and financial implications have not yet been finalised.

The scheme for Development of Winter Sports at Gulmarg is primarily intended to attract larger number of foreign tourists to India. However, the facilities will be open to all tourists including home tourists.

Wagons for Timber in Punjab

1185. Shri Daljit Singh: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether the timber trade of Punjab has been heavily affected due to shortage of wagons; and

(b) if so, what steps have been taken to supply more wagons?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Post Offices in Punjab

1186. Shri Daljit Singh: Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state:

(a) the number of new post offices opened in rural areas in Punjab during 1961-62; and

(b) the number of new post offices proposed to be opened in rural areas of Punjab during 1962-63?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Communications (Shri Bhagavati): (a) 284.

(b) 195.

Telephone Connections at Nangal

1187. Shri Daljit Singh: Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state:

(a) the number of persons who have applied for telephone connections at Nangal township (Punjab) and have not been provided with telephones so far; and

(b) when they are likely to be provided with telephones?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Communications (Shri Bhagavati): (a) 16.

(b) The connections will be given after opening of the new exchange at Naya Nangal which will give relief to Nangal area. It is not possible to give any definite date at this stage due to uncertainty supply of stores.

Dam Across Jamuna near Okhla

1188. Shri D. C. Sharma: Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

(a) whether a scheme for the construction of a barrage across the Jamuna, near Okhla, to stabilise the course of the river and ensure an adequate water supply for the Central Power House and its cooling plants at Rajghat is under consideration by the Central Water and Power Commission; and

(b) if so, the details of the scheme and the stage at which the matter stands at present?

The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Alagesan): (a) Yes.

(b) Details of the scheme have yet to be finalised. At present model

experiments are being conducted at Poona Research Station.

Smallpox in Assam

1189. Shri Basumatari: Will the Minister of Health be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a programme for eradication of Smallpox in Assam is under way;

(b) if so, into how many phases the programme will be conducted; and

(c) which will be the administrative districts to be covered in the first phase of programme?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) Yes.

(b) The programme is being conducted in two phases.

(c) Four units will work during the first phase and will cover the following five districts:

- (1) Goalpara
- (2) Nowgong
- (3) Sibsagar
- (4) Garo Hills and
- (5) United Mikir and North Cachar Hills.

कलकत्ता से मुगलसराय तक बिजली की रेलगाड़ियां

११६०. श्री प्रकाशबीर शास्त्री : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता से मुगलसराय तक बिजली से रेल चलाने का काम पूरा हो चुका है, और यदि हां, तो कब तक हो जायेगा ;

(ख) क्या इसी वर्ष में बिजली से इस लाइन पर गाड़ियां चलने लगेंगी और, यदि हां, तो कब से ;

(ग) क्या इस बिजली से गाड़ी चलने वाली योजना को और भी बढ़ाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और कब तक वह पूर्ण हो जायेगी ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० बें० रामस्वामी) : (क) हावड़ा-बंडेल-बर्दवान सेक्शन पर (मेन लाइन के रास्ते) ३००० वोल्ट डी० पी० प्रणाली के अनुसार बिजली लगायी जा चुकी है और दुर्गापुर-मुगलसराय सेक्शन पर भी २५ किलोवाट ए० सी० प्रणाली के अनुसार बिजली लगायी गयी है। आशा है कि दिसम्बर, १९६४ तक बर्दवान - दुर्गापुर के बाकी टुकड़े पर भी बिजली लगाने का काम पूरा हो जायेगा।

(ख) हावड़ा बर्दवान सेक्शन पर १९५९ से बिजली की गाड़ियां चल रही हैं। दुर्गापुर-मुगलसराय सेक्शन पर मार्च, १९६१ और जुलाई, १९६२ के बीच अलग अलग चरणों में बिजली लगायी गयी थी और माल गाड़ियों को बिजली द्वारा चलाने की व्यवस्था की जा रही है।

(ख) और (घ) नीचे लिखे सैक्शनों पर या तो बिजली लगायी जा चुकी है या तीसरी आयोजना के दौरान उन पर बिजली लगाने का कार्यक्रम बनाया गया है और नियत तिथि हर एक के सामने दी गयी है :—

	माग किलोमीटर	नियत तिथि
दक्षिण-पूर्व-रेलवे		
भासनसोल-सिनी-टाटानगर-राउरकेला, जिसमें राज खरसवां-दांगोपोसी सेक्शन (माग कि० मी० ७५) शामिल नहीं है, जहां दूसरी आयोजना की अवधि में बिजली लगायी गयी थी।	३३२	बिजली गाड़ियां चलाना अलग-अलग चरणों में पहले ही शुरू हो चुका है।
खड़गपुर-टाटानगर	१३३	१९६२ के अन्त तक
हावड़ा-खड़गपुर	११५	दिसम्बर, १९६५
अतिरिक्त शाखा लाइनें	१७२	१९६२ के अन्त से मार्च, १९६४ तक
पूर्व रेलवे		
सियालदह -रानाघाट: दमदम-बनगांव	१४३	जन, १९६३
सियालदह (दक्षिण)	१८७	मार्च, १९६५
वारिया-बर्दवान डॉक्स	१९७	दिसम्बर, १९६४
उत्तर रेलवे		
मुगलसराय-इलाहाबाद	३४९	सितम्बर, १९६४
और		
लाहबाद-कानपुर		सितम्बर, १९६५
मध्य रेलवे		
इगतपुरी-नंद गांव	३०८	जून, १९६५
नंदगांव-भुसावल		मार्च, १९६६
दक्षिण रेलवे		
मद्रास-ताम्बरम्-विष्णुपुरम्	१६०	दिसम्बर, १९६३

Port Charges

1191. Shri P. K. Deo: Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state:

(a) whether the merchants chamber of Calcutta has urged that uniform charges be levied at different Indian ports;

(b) whether port charges are different in different ports in this country; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Minister of Shipping in the Ministry of Transport and Communications (Shri Raj Bahadur): (a) No. Government have not received any representation on the subject from the Merchants Chamber of Commerce.

(b) Yes.

(c) Port charges are fixed basically with reference to the cost of maintaining the Port. They may, however, vary from commodity to commodity at different Ports regard being had to a number of factors such as the quantum of traffic, nature of the cargo, method of handling, and the extent to which it can bear a charge, in the light of considerations such as export promotion or in the case of imports essentiality of the commodity to the public.

Thermal Plant at Ennore (Madras)

1192. Shri P. K. Deo: Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

(a) whether a Thermal Plant is going to be established at Ennore at the request of Madras Government; and

(b) if so, from where coal will be supplied for the Thermal Plant?

The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Alagesan): (a) No.

(b) Does not arise.

1531 (A) L.S.D.I.—15.

Agriculture in Himachal Pradesh

1193. Shri Hem Raj: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether the West German Team of Experts on Agriculture has started its work for the development of Agriculture in the Mandi District of Himachal Pradesh; and

(b) how its beneficial results will be made available for the use of the contiguous hill areas of Punjab and Uttar Pradesh?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Not yet.

(b) It is too early to consider this. This would arise only after the programme has been in operation for sometime and proves successful.

Porters at Pathankot Railway Station

1194. Shri Hem Raj: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) the number of porters who were sanctioned for Pathankot Railway Station in 1960;

(b) the number increased in 1961 and 1962 separately;

(c) whether the porters union of Pathankot represented to the Railway authorities for the constitution of a co-ordination committee of the porters and railway officials just like one constituted at Jullundur; and

(d) if so, the action taken thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shah Nawaz Khan): (a) 85.

(b) The number was increased to 95 in May, 1961 and to 120 between April and November with effect from June, 1962.

(c) and (d). Yes. A committee has been formed on the lines of that as at Jullundur.

Quarters for P&T Employees

1195. **Shri P. Kanhan:** Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state the total number of departmental quarters constructed for P&T employees in the

country as a whole as well as circle-wise, during the last five years, each year separately?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Communications (Shri Bhagavati):

Name of Circle	Number of Units constructed during the last Five years					Total
	1957-58	1958-59	1959-60	1960-61	1961-62	
Assam	65	75	30	32	27	229
Andhra	12		1	44		57
Bihar	4	10				14
Bombay	11	6		24	492	533
Central	40	3				43
Delhi	40		12	14	36	102
Gujarat				2	154	156
Kerala	8	2	5	3	4	22
Madras		7	2	5		14
Mysore	25	2			2	29
Orissa	10	1	4	15
Punjab	15	202	44		9	270
Rajasthan				66	3	69
U.P.	39	27	128	119	21	334
West Bengal	8	4	1	7	9	30
Calcutta District	14	12			12	38
Bombay District					99	99
GRAND TOTAL						2054

Mechanised Fishing Boats

1196. **Shri A. K. Gopalan:** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether Government have sanctioned any scheme for the subsidised sale of mechanised fishing boats to the Lacadive Islanders; and

(b) if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas): (a). Yes.

(b) the scheme involves grant of 100 per cent subsidy on engines and 25 per cent subsidy on hulls of mechanised fishing boats. The cost of boats and the subsidies are as follows:

Details	Total average Cost	Subsidy	Sanctioned cost
25' boats	Rs. 14,336/-	Rs. 7,374/-	Rs. 6,962/-
30' boats	Rs. 22,195/-	Rs. 12,051/-	Rs. 10,144/-

Manufacture of Emergency Lighting Equipment

1197. Shri P. K. Deo: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether lately emergency lighting equipment has been manufactured in the South Eastern Railway Workshop and has been provided in the trains to facilitate relief operation at times of accident at night;

(b) in which of the trains this facility has been provided; and

(c) whether similar facilities have been extended to other railways?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan): (a). Yes.

(b). On all Broad Gauge Mail, Express and long distance main line passenger trains on the South Eastern Railway.

(c). Yes. This equipment is being progressively installed on passenger trains on the Indian Railways.

Attendants in Corridor Coaches

1198. Shri P. K. Deo: Will the Minister of Railways be pleased to state whether attendants have been provided in all the first class corridor coaches in the trains?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan): As a first step, Attendants are being provided, in the I Class corridor coaches on some important trains.

Price of Fertilizers

1199. Shri R. S. Pandey: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether there is any disparity in the retail prices of ammonium sulphate and other fertilizers supplied to agriculturists and plantations; and

(b) if so, whether there is any proposal to eliminate the disparity?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh): (a). Yes, a statement is placed on the Table of the House. [See Appendix II, annexure No. 17].

(b). The matter is under consideration.

Alopecia Universalis

1200. Dr. L. M. Singhvi: Will the Minister of Health be pleased to state:

(a) whether any facilities exist in India for the treatment and cure of Alopecia Universalis;

(b) whether Government are aware of various surgical and clinical advances abroad in the treatment of this ailment;

(c) whether anything is being done to promote similar experiments and lines of treatment in this country; and

(d) whether there is any definite data regarding the incidence of this disease in India and the main causes of it?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) to (d). Facilities for the treatment of Alopecia Universalis exist in all general hospitals in the country. There is no specific cure for this disease but certain groups of the cortisone family of drugs give relief in some cases. However, the steroid effect is not permanent and Alopecia Universalis recurs if the maintenance dose is lowered to 6 mgm. Continuous use of cortisone is also not advisable.

There are no data available with regard to the incidence of this disease. It is congenital in some cases and the disease is also acquired through psychological or toxic conditions.

उज्जैन-आगरा छोटी लाइन

१२०१. श्री बड़े : क्या रेलवे यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उज्जैन-आगर छोटी लाइन में १९५८ से १९६१ तक अलग अलग प्रतिवर्ष कितना खर्च एवं कितनी आमदनी हुई;

(ख) क्या यह सच है कि उज्जैन से छतरपुर, आगर हो कर बड़ी लाइन की कोई रूपरेखा सरकार के सामने है; और

(ग) यदि हां, तो उस का क्या विवरण है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह-नवाज खां) : (क)

हजार
(रुपयों में)

वर्ष	खर्च	आमदनी
*१९५८-५९	३,२१	१,८९
*१९५९-६०	३,४०	१,६६
(संशोधित आंकड़े)		
*१९६०-६१	२,९०	१,८९

(*) ये आंकड़े आनुमानिक आधार पर निकाले गये हैं, क्योंकि रेलवे लाइनों के हर सैक्शन के खर्च और आमदनी का निश्चित हिसाब अलग अलग नहीं रखा जाता।

(ख) जी नहीं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

प्रतीक्षालय

१२०२. श्री बड़े : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के जावद रोड स्टेशन (नीमच-अजमेर लाइन) पर प्रतीक्षालय नहीं है;

(ख) क्या इस विषय में अनेक अभ्या-वेदन प्राप्त हुए थे; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह-नवाज खां) : (क) शायद माननीय सदस्य का मतलब ऊंचे दर्जे के यात्रियों के लिये प्रतीक्षालय की व्यवस्था से है। यदि ऐसा है, तो इस का उत्तर है, हां।

(ख) जी हां।

(ग) इस बारे में जांच की गयी थी जिस से पता चला कि इस स्टेशन पर आने-जाने वाले ऊंचे दर्जे के यात्रियों की संख्या को देखते हुए यहां ऊंचे दर्जे का प्रतीक्षालय बनाने का औचित्य नहीं है। इस की सूचना प्रतिवेदन करने वालों को दे दी गयी थी।

Quarters for Railway Employees in Delhi

1203. Shri Shiv Charan Gupta: Will the Minister of Railways be pleased state:

(a) how many quarters and at which places have been constructed in Delhi for railway employees in the First and Second Plan periods;

(b) whether these quarters have been electrified; and

(c) whether electric fans have been provided in them?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan): (a). The total number of quarters constructed so far in Delhi area for Railway employees is 7773. The exact number of quarters which were constructed during the First and Second Plan periods is not immediately available. This information is being collected and will be placed on the table of the House later.

These quarters have been constructed in the following localities of Delhi:

Delhi, New Delhi, Delhi Kishan-ganj, Dayabasti, Shakurbasti, Subzimandi, Nizamuddin, Tughlakabad, Lajpat Nagar, Sewa Nagar, Lodi Colony, Sarojni Nagar, Delhi Safdar-

jang, Sardar Patel Road, Tilak Bridge, College Lane, Basant Lane, Chelmsford Road, Pachkuin Road, Boulevard Road, Siri Ram Road, Delhi Queens Road, Sarai Phus, Delhi Sarai Rohilla, Delhi Lahori Gate, Motia Bagh, Hamilton Road, More Sarai, Patel Nagar, Delhi Cantt., Palam, Minto Bridge and College Lane.

(b) About 88 per cent of them have been electrified.

(c) Electric fans have been provided in approximately 40.5 per cent of the quarters.

Cracks in Ahmedabad Railway Station Buildings

1204. **Shri Raghunath Singh:** Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that big cracks were detected in the newly constructed buildings of Ahmedabad Railway Station (Metre gauge) on Western Railway; and

(b) if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shah Nawaz Khan): (a) and (b). No, Sir. However, a small hair-crack between the RCC beam and the brick filling underneath it in the third class waiting hall, was noticed. This is caused by temperature changes and has no structural significance.

Draught in Lower Damodar Belt

1205. **Shri Dinan Bhattacharya:** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

(a) whether Government are aware of regular draught in the lower belt of Damodar since the day of commissioning of Damodar Valley Corporation Project; and

(b) if so, whether Government or Damodar Valley Corporation has any plan to improve the situation there?

The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Alagesan): (a). No.

(b). Does not arise.

Dacoity in P.O. Hojai (Assam)

1206. **Shri P. C. Borooah:** Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a darning dacoity was committed on 28th-29th July, 1962 in the Post and Telegraph Office at Hojai in Assam;

(b) if so, how much amount was looted and how many persons were injured in the dacoity; and

(c) whether the culprits have been brought to book?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Communications (Shri Bhagavati): (a) Yes Sir.

(b) Rs. 5483.24 nP. The Sub Postmaster was injured.

(c) The Police have apprehended five suspects.

आदिम जाति क्षेत्रों में जनस्वास्थ्य

१२०७. **श्री उदिया :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रके आदिवासी प्रधान क्षेत्रों में जनस्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु सरकार ने क्या विशेष प्रयास १५ जुलाई, १९६२ तक किये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Bhakra Dam Project

1208. **Shri D. C. Sharma:** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

(a) whether compensation to all those who have been affected by the Bhakra Dam Project has been made; and

(b) if so, the total amount that has been paid?

The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Alagesan): (a) Compensation has been paid to all the persons affected by the Bhakra Dam Project except those who have appealed to Civil Courts for enhancement of compensation offered to them or those who have not so far come forward to receive payment.

(b) Rs. 2,99,01,758.

Rates of Electricity in Delhi

1209. Shri D. C. Sharma: Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state the progress made in the matter of having uniform rates for light and fans, domestic power and industrial power in the Union Territory of Delhi?

The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Alagesan): The question whether the rates being charged by the New Delhi Municipal Committee can be brought down to the level of those in force in the area served by the Delhi Electric Supply Undertaking is under examination. A Committee was appointed to examine the financial operations of the Electricity Department of the New Delhi Municipal Committee. Its report is awaited.

Narela and Shahdara in the Union territory of Delhi are served by private licensees. As their cost of generation and supply of electricity is higher than that of the Delhi Electric Supply Undertaking, they cannot be forced to adopt the rates charged by the latter.

Rickshaw Pullers, Society

1210. Shri D. C. Sharma: Will the Minister of Community Development, Panchayati Raj and Co-operation be pleased to state:

(a) whether a rickshaw pullers' society will be established in Delhi;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) the extent and nature of financial assistance contemplated?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development, Panchayati Raj and Co-operation (Shri Shyam Dhar Misra): (a) There are already four rickshaw pullers' co-operative societies in Delhi.

(b) The question does not arise.

(c) Delhi Administration have proposed to give financial assistance to one society as per approved pattern according to which a sum of Rs. 20,000 may be given as loan for purchase of rickshaws and a sum of Rs. 900 as subsidy towards managerial expenses to a society.

Consumption of Electricity in Punjab

1211. Shri D. C. Sharma: Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

(a) the *per capita* consumption of electricity in Punjab as on the 1st August, 1962; and

(b) the reasons for such low consumption?

The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Alagesan): (a) and (b). The figures in respect of *per capita* consumption as on 1st August, 1962, have not yet been compiled. The *per capita* consumption in Punjab during 1961-62 was about 62.8 kWh, which was higher than that of most of the other States.

Printing of Air India Booklets Abroad

1212. { Shri Kajrolkar:
 { Shri Raghunath Singh:
 { Shri R. P. Singh:
 { Shri U. M. Trivedi:

Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state:

(a) the total amount spent by the Air India each year in getting brochures, books, folders, posters, tickets printed abroad;

(b) the reasons for printing these booklets abroad; and

(c) the amount of foreign exchange involved therein?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Communications (Shri Bhagavati): (a) The approximate amount spent by Air India Corporation during the years 1959-60, 1960-61 and 1961-62 on getting time-tables, tickets, brochures, folders etc. printed abroad is given below:—

1959-60	1960-61	1961-62
Rs. 6,37,500	Rs. 8,29,000	Rs. 12,24,400

(b) The reasons for printing these articles abroad are as under:—

- (i) *Time-tables*: Time-tables issued by the Corporation in Europe contain both English version as also a version in the local language of the country namely French, German, Italian etc. These used to be got printed in Geneva because of easy availability of necessary facilities. The Corporation have, however, started printing the full size time-tables in India to save foreign exchange expenditure.

(ii) *Passenger tickets, excess baggage tickets, Miscellaneous Charges Orders and Coupons*: These require a special type of carbon paper backing which is not produced in India. The orders for printing these articles were, therefore, placed with a Japanese firm whose quotations were the lowest. However, the possibility of getting the required type of carbon paper produced in India is being explored by the Development Wing of the Ministry of Commerce and Industry.

(iii) *The Special Boeing Brochure*: The specialised part of job was the coloured tissue paper which also is not produced in India. Global tenders were invited for this item and the lowest tender was received from a Japanese firm on whom the order was finally placed.

(iv) *Sales letter, tour folders, bulletins etc.*: The material for these items depends largely on local needs. They essentially form part of the publicity campaigns undertaken by the outstation offices of the Corporation. The printing of such items in India would not only be inconvenient but also expensive and the delays which would inevitably be involved in getting them printed in India and then despatching them to foreign stations would defeat their purpose. For competitive reasons it is necessary to get these printed locally so that they are available according to the required time schedule.

(c) The amounts indicated under (a) above represent foreign exchange expenditure in full.

Notes: (1) The amount indicated in reply to part (a) of the question includes expenditure on certain other items like postage, transport charges etc., as no separate accounts of expenditure incurred on such items is maintained by the Corporation.

- (2) During 1959-60, New York was an off-line point and, therefore, the expenditure on publicity items was much less. New York functioned as an on-line station for a part of the year 1960-61 and the expenditure increased during that year. In the year 1961-62, in addition to New York functioning as a regular on-line station with as many as five services a week during on-season and 3 during off-season, a number of sales offices were opened in the U.S.A. There has, therefore, been an inevitable increase in the expenditure on sales promotional items.

Shuttle Service for Delhi Students Studying at Ghaziabad

1213. Shri Solanki: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a shuttle service from Ghaziabad to Delhi for Delhi students reading in various colleges in Ghaziabad;

(b) if so, whether separate compartments have been provided for ladies in it;

(c) whether it is also not a fact that in ladies compartments the boys outnumber the girls; and

(d) if so, why railway police personnel and officers are not posted to check this so as to avoid harassment to ladies?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan): (a) There is no shuttle train exclusively for students between Ghaziabad and Delhi. However, 331 Up New Delhi-Amritsar Passenger Train which starts from New Delhi at 5.05 hours and reaches Ghaziabad at 6.37 hours caters for students attending schools and colleges at Ghaziabad in the morning shift. In addition to this, students travel by other trains between Delhi and Ghaziabad according to the various shifts in the schools and colleges at Ghaziabad.

(b) Yes.

(c) While boys below the age of 12 years are permitted to travel in ladies compartments, it has not come to notice that the boys outnumber the girls in such compartments.

(d) Extant rules provide for ladies' compartments being occupied only by those who are entitled to travel in them. Necessary staff has been detailed for ensuring that the rules are observed and assistance of police is sought, should necessity arise.

Medical Colleges

1214. Shri Naval Prabhakar: Will the Minister of Health be pleased to state:

(a) whether it is a fact that seats in medical colleges for M.B.B.S. Course have been reserved for students belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(b) if so, what steps Government take to get the required number of students from such communities; and

(c) whether some organisations are also asked to give publicity for getting such students?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) Yes; seats have been reserved for candidates belonging to

Scheduled Castes and Scheduled Tribes in almost all the Medical Colleges.

(b) and (c). Due publicity is given through newspapers and the Prospectus of the College concerned.

Prices of Pure Ghee in Delhi

1215. { **Shri A. V. Raghavan:**
Shri Pottekkatt:

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the rise in prices of pure ghee in the New Delhi Market; and

(b) what steps Government propose to take to bring down the prices?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas): (a) Yes.

(b) It is not proposed to take any direct regulatory measures. It is hoped, however, that the country-wide planned increases in milk production, oilseeds production and dairy development will help relieve the situation indirectly.

Exchange of Animals with Netherlands

1216. **Shri Man Singh P. Patel:** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether there was any agreement to exchange tigers and cranes of Delhi Zoological Park for other continental animals with any private firm of Netherlands;

(b) if so, the details thereof; and

(c) how far the agreement has been carried out?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Yes, Sir.

(b) A barter arrangement was made in 1960 by the Delhi Zoological Park with Messrs Van Den Brink, a reputed firm of Holland dealing in animals and birds, for procurement of 6 Macaw Parrots, 24 Pheasants and a pair of

Chimpanzees in exchange of one pair of Tiger cubs, 5 Spotted Deer, 35 Saras Crane and 2 pairs of Leopards. The value of the barter deal was Rs. 9,120.

(c) Two Tiger cubs and 20 Saras Cranes valued at Rs. 4,726 were despatched by the Delhi Zoological Park. In return, 13 Pheasants and 6 Macaw Parrots valued at Rs. 3,330 were obtained from the Dutch firm. In view of the Dutch Government's ban on the import of split-hoofed animals into their country, the firm expressed its inability to complete the deal on the lines originally agreed upon. They were prepared to adjust the difference either in cash or by supplying other species. It is now proposed to close the deal by obtaining 10 rare Pheasants valued at Rs. 1,396 from the firm to cover the balance outstanding.

Mango crop in Bihar

1217. **Shrimati Ramdulari Sinha:** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there has been exceptionally bumper mango crop throughout the State of Bihar this year;

(b) if so, in what other States there has been similar mango season; and

(c) reasons which have contributed to such good harvest of mangoes?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh): (a) to (c). This year the mango crop was exceptionally good in certain States for example Bihar. However, the information is being collected from all the States and will be placed on the Table of the Sabha.

गन्ने की कीमत

१२१८. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२ के मौसम में किस राज्य में वास्तव में किस दर पर गन्ने के दाम दिये गये हैं;

(ख) एक राज्य से दूसरे राज्य के दाम में अन्तर होने का क्या कारण है;

(ग) प्रत्येक राज्य में गन्ने की खेती में प्रति एकड़ औसतन क्या खर्चा पड़ता है ; और

(घ) किस राज्य में किसानों के गन्ने का कितना दाम बाकी है और उसे भुगतान करने का क्या प्रबन्ध हो रहा है ?

साख तथा कृषि मंत्रालय में उपसंजी (ओ.ओ.म.०.यामस) : (क) और (ख). १९६१-६२ में महाराष्ट्र और गुजरात को छोड़ कर समस्त भारत में गन्ने की मिल के दरवाजे पर पहुँच की न्यूनतम कीमत १ रु० ६२ न० पै० प्रति मन और रेल स्थित केन्द्रों

पर १ रु० ५० न० पै० प्रति मन थी। मिलों ने सड़क से गन्ना ले जाने का खर्चा काट कर यही कीमतें चुकाई थीं। पहली मई के बाद पेरे गये गन्ने पर साप्ताहिक उपलब्धि में प्रत्येक ०.१ प्रतिशत की कमी होने से उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब में १.५ न० पै० प्रति मन की छूट सप्ताह में ६ प्रतिशत से कम उपलब्धि होने पर दी जाती थी। इसके अतिरिक्त गन्ना उत्पादक, यदि वे इस के हकदार थे तो विलम्बित भुगतान के अधिकारी भी थे। महाराष्ट्र और गुजरात में समेकित कीमत (न्यूनतम कीमत जमा विलम्बित भुगतान) नियत है और पिछली फसल की उपलब्धि के आधार पर १९६१-६२ में मिलों द्वारा दी जाने वाली कीमत यह थी :—

महाराष्ट्र

गुजरात

(रुपये प्रति टन)		(रुपये प्रति टन)	
११ प्रतिशत से कम उपलब्धि	५२।-	१० प्रतिशत से कम की उपलब्धि	४८।--
११ प्रतिशत और इससे अधिक लेकिन ११.५ प्रतिशत से कम की उपलब्धि	५३।-	१० प्रतिशत और इससे अधिक लेकिन १०.५ प्रतिशत से कम की उपलब्धि	५०।-
११.५ प्रतिशत और इससे अधिक लेकिन १२ प्रतिशत से कम की उपलब्धि	५४।-	१०.५ प्रतिशत और इससे अधिक लेकिन ११ प्रतिशत से कम की उपलब्धि	५२।-
१२ प्रतिशत और इससे अधिक लेकिन १२.५ प्रतिशत से कम की उपलब्धि	५५।-	११ प्रतिशत और इससे अधिक किन्तु ११.५ प्रतिशत से कम की उपलब्धि	५३।-
१२.५ प्रतिशत और इससे अधिक की उपलब्धि	५६।-	११.५ प्रतिशत और इससे अधिक लेकिन १२ प्रतिशत से कम की उपलब्धि	५४।-
		१२ प्रतिशत और इससे अधिक लेकिन १२.५ प्रतिशत से कम की उपलब्धि	५५।-
		१२.५ प्रतिशत और इससे अधिक की उपलब्धि	५६।-

(ग) प्रत्येक राज्य में गन्ने के उत्पादन के विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) १५ जुलाई १९६२ को १९६१-६२ की फसल की अपेक्षित सूचना का विवरण

सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १८]

गन्ने की पिछली शेष कीमत का शीघ्र भुगतान करने के लिये राज्य सरकारों को कह दिया गया है।

Muzaffarpur R.M.S. Building

1219. Shrimati Ramdulari Sinha: Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state:

(a) whether there is no provision of latrine and water supply in Muzaffarpur R.M.S. building for the last three years;

(b) if so, what arrangement is being made in this regard;

(c) how many R.M.S. offices are functioning in 'W' Division of Bihar Postal circle with or without latrines; and

(d) when the proposal for providing latrines in these buildings is expected to materialise?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Communications (Shri Bhagavati): (a) A latrine and water tap existed in the Muzaffarpur R.M.S. building but the same were dismantled in August 1960, when the extension of the building was taken up. After their dismantlement the staff are using the latrine for the general public situated at the Railway Platform. So far as supply of water is concerned, there is water tap close to the mail office and a waterman stores water for drinking and other purposes.

(b) Proposals for provision of latrine and water facilities at Muzaffarpur R.M.S. building are at an advanced stage and the matter is being pursued vigorously with the Railways.

(c) Presumably the reference is to 'U' Division as 'W' Division is in Gujarat Circle. Latrines have been provided in the R.M.S. offices at Chapra, Darbhanga, Samastipur and Mansi. The R.M.S. Offices at Sonapur, Muzaffarpur, Barauni and Katihar have not yet been provided with latrines.

(d) The Railways had earlier declined to provide latrines at Barauni and Katihar. Provision of these facilities at these Stations as well as at Sonapur will be pursued with the Railways. Regarding Muzaffarpur, the position has already been explained in part (b) above.

Willingdon Hospital, New Delhi

1221. Shri D. C. Sharma: Will the Minister of Health be pleased to state:

(a) the average number of patients per day being treated in Willingdon Hospital, New Delhi, during the past three months;

(b) whether the number of patients is on the increase;

(c) the number of persons on the staff of the hospital;

(d) whether Government consider the number of persons on the staff adequate to deal with the number of patients; and

(e) if not, what steps Government propose to take to meet the increasing demands on the hospital staff?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar):

(a) May, 1962	1785
June, 1962	1732
July, 1962	1831
(b) Yes.	/
(c) Classes I & II	40
Class III	226
Class IV	330

(d) and (e). Yes. The requirements of the Casualty and Out-patient Departments, however, are being reviewed in view of the considerable increase in the number of patients.

Central River Board Committee

1222. Dr. P. Srinivasan: Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to constitute a Central River Board Committee;

(b) if so, what will be the nature and functions of the Committee; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Alagesan): (a) No.

(b) Does not arise.

(c) The River Boards Act, 1956, under which the Government of India

propose to set up River Boards for certain important inter-State river Basins in the country, does not provide for the establishment of any Central River Board Committee as envisaged in part (a) of the question.

Major Rivers in India

1223. Dr. P. Srinivasan: Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

(a) how many major rivers are there in India; and

(b) what is the percentage of water utilised from them for (i) irrigation, (ii) power, (iii) drinking purpose and (iv) wastage into the seas?

The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Alagesan): (a) The major rivers in India excluding their tributaries are given below:—

1. Indus Basin Rivers.
2. Ganges.
3. Brahmaputra.
4. Mahanadi.
5. Krishna.
6. Cauvery.
7. Tapi or Tapti.
8. Narmada.
9. Godavari.

and 10. Damodar.

(b) No detailed assessment of the water resources of all the rivers and their utilisation for different purposes has so far been made. However, it has been estimated that

- (i) by the end of the Second Plan about 27 per cent of the usable flow or 8.9 per cent of the total annual flow of the entire river water resources of the country would have been utilised by the end of the Second Plan.
- (ii) The utilisation for generation of hydro power is at present about 4 per cent of the average total annual flow of all rivers.
- (iii) and (iv) No information is available.

Providing of Level Crossing at New Barrackpur Halt Station

1224. Shrimati Renu Chakravartty: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there are heavy casualties on the Eastern Railway suburban lines due to people walking on the railway tracks;

(b) whether it is a fact that the heavy growth of population on either side of new Barrackpur halt station on Eastern Railway leads to people indiscriminately crossing the track as there is no railway gate to control traffic when trains are approaching;

(c) whether it is a fact that the girls of college and the boys of school are on opposite sides of the track and children cross the track without any control;

(d) whether the bazar is also situated by the side of the track; and

(e) whether Government have considered the desirability of putting a railway gate at this point for the safety of the people, specially the children?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy):

(a) Some trespassers at times get killed while they attempt to cross the Railway line.

(b) to (e). Yes, Sir. It has not been found feasible to prevent trespassing as persons cross the lines by short-cut and not at particular crossings.

Linking of Basirhat-Barasat Railway with Sealdah

1225. Shrimati Renu Chakravartty: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether the Basirhat-Barasat railway will be directly linked with Sealdah by drawing the coaches by electric engines from Barasat to Sealdah;

(b) how far will this reduce the number of trains on the Bongaon section after electrification; and

(c) whether the question of doubling railway track between Barasat and Dumdum is still under consideration?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy):

(a) No, Sir; not for the present.

(b) Does not arise.

(c) There is no such proposal under consideration. The doubling of the section will be considered only when

(a) No, Sir; not for the present.

रेलगाड़ियों में महिला डिब्बे

१२२६. श्री बंरवा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब कि सरकार की ओर से स्त्रियों को समान अधिकार दिये गये हैं और पर्दा प्रथा भी बन्द कर दी गई है तो इन के लिये रेलवे में अलग डिब्बा क्यों लगाया जाता है जब कि अलग डिब्बों में कई बार बदमाश चोरी कर ले जाते हैं और स्त्रियों के अकेली बैठी रहने के कारण कई हत्यायें भी हुई हैं;

(ख) इस बारे में सरकार ने क्या सोचा है और इन लूट मार की घटनाओं से बचाने के लिये सरकार ने क्या प्रवन्ध किया है ;

(ग) क्या अलग रखे जाने वाले स्त्रियों के डिब्बे समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो यह कब से समाप्त कर दिये जायेंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) रेल प्रशासनों पर यह एक सांविधिक दायित्व है (देखिये १८६० के भारतीय रेल अधिनियम ६ की धारा ६४) कि वे यात्रियों को ले जाने वाली प्रत्येक गाड़ी में केवल महिला यात्रियों के इस्तेमाल के लिये, गाड़ी के अंग के रूप में, कब से कम सब से निचले दर्जे का अलग डिब्बा लगाने की व्यवस्था करें। इस सुविधा से महिला यात्रियों की आवश्यकता पूरी हो जाती है, विशेष

रूप से उन महिला यात्रियों की जिन के साथ कोई पुरुष सम्बन्धी यात्रा नहीं करते और जो महिलाओं को अलग डिब्बे में यात्रा करना पसन्द करती हैं।

इन अलग डिब्बों में यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिये इन में सुरक्षा की यथासम्भव पूरी व्यवस्था रहती है। एक बयान सभा के पटल पर रखा जाता है जिस में विस्तार से बताया गया है कि महिलाओं के लिये नियत अलग डिब्बे में यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिये क्या उपाय अपनाये गये हैं। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १६]

(ग) जी, नहीं।

(घ) महिलाओं के लिये डिब्बों का आरक्षण महिलाओं के हित में आवश्यक समझा गया है। यह सुविधा समाप्त करने से उन्हें बहुत बड़ी असुविधा होने की आशंका है।

स्टेशनों पर स्वच्छ पानी का प्रबन्ध

१२२७. श्री बंरवा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जहां स्टेशनों पर पानी की टंकियां बनी हुई हैं और उन्हीं से कनेक्शन किये हुए स्टेशनों पर नल लगा रखे हैं क्या वह पानी स्वच्छ होता है;

(ख) यदि नहीं, तो क्यों नहीं और क्या सरकार ने कभी इस के बारे में सोचा है;

(ग) यदि सरकार अब पानी स्वच्छ रखने का विचार रखती है तो ऐसा कब से किया जायेगा; और

(घ) यह पानी की टंकियां कब साफ की जाती हैं और इनके साफ करने की क्या प्रवधि है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं, सभी स्टेशनों पर नहीं।

(ख) पानी को पीने के योग्य बनाने के लिए सभी स्टेशनों पर उसे छानना जरूरी नहीं है। जब कभी आवश्यकता समझी जाती है, पानी छान लिया जाता है।

(ग) ऊपर भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

(घ) तीन महीने से लेकर छः महीने के अन्दर टंकियों को एक बार खुरचकर पूरी तरह साफ किया जाता है। यह सफाई टंकियों में जमा हो जाने वाली गाद की मात्रा के आधार पर की जाती है। विशेष स्थितियों में सफाई इस से भी कम अन्तर पर की जाती है। जहाँ आवश्यक होता है टंकियों को रोगाणु-नाशक दवाई से भी साफ किया जाता है।

बारां स्टेशन पर रेलकर्मचारी की गाड़ी से हब कर मृत्यु

१२२८. श्री बंरवा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक १४ जुलाई, १९६२ को बारां स्टेशन पर एक रेलवे कर्मचारी अपनी ड्यूटी देते हुए शाम की गाड़ी से कट कर मर गया;

(ख) यदि हां, तो उसके बच्चों के लिए सरकार की ओर से क्या प्रबन्ध किया जायगा; और

(ग) यह प्रबन्ध कब तक किया जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सॅ० बॅ० रामस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). मृत कर्मचारी के आश्रितों को कामगार मभावजा एकट के अर्धीन ३,००० रुपय मुभावजा दिया जायगा। यह रकम कामगार मभावजा कमिश्नर कोटा के पास ३१ अगस्त, १९६२ से पहले जमा करा दी जायेगी।

मृत व्यक्ति के निर्वाह-निधि केखाते में १४६२ रु० ६५ न० पै० की रकम उसके नामित या वैध उत्तराधिकारी को देय है। इसके अलावा निर्वाह-निधि में विशेष अंशदान के ६०० रु० भी उसके आश्रितों को देय है। आवश्यक औपचारिक कार्रवाइयों के पूरा होने पर इन दोनों रकमों का भुगतान कर दिया जायेगा।

पश्चिम रेलवे में सन् १९६१ में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की नियुक्ति

१२२९. श्री बंरवा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९६१ में कितने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को पश्चिम रेलवे में नौकरियां दी गईं; और

(ख) इसी अवधि में अन्य जाति के कितने व्यक्तियों को उक्त रेलवे में नौकरियां दी गईं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह-नवाज खां) :

(क) दर्जा ३	११३
दर्जा ४	४४०
(ख) दर्जा ३	८०५
दर्जा ४	४०६४

रासायनिक खाद से पैदा की गई फसलें

१२३०. श्री बंरवा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो फसलें रासायनिक खाद व दवाइयां डालकर पैदा की जाती हैं इनका मनुष्यों और पशुओं के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : यदि रासायनिक उर्वरकों का सविवेक प्रयोग किया जाये तो मनुष्यों और पशुओं के स्वास्थ्य पर

कोई बुरा प्रभाव नहीं होता है। वास्तव में फास्फोरस पूरक जैसे कुछ उर्वरकों के प्रयोग से कुछ अनुकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, जिस से पौधों की पोषणिक कमी हो दूर किया जा सकेगा और अन्ततः उनके प्रयोग द्वारा मनुष्यों और पशुओं शरीर में भी इस कमी को पूरा किया जा सकेगा।

जहां तक दवाइयों का सम्बन्ध है (अनुमान है कि इस स्थान पर दवाईयो का तात्पर्य फफूंदनाशी, कीटनाशी, खरपतवार नाशी और बढ़ौत्तरी-नियामकों से है) केवल फफूंदनाशी, कीटनाशी, खरपतवार नामी और बढ़ौत्तरी-नियामकों जैसी दवाईयो की वनस्पति-रक्षा में उपयोग करने के लिए सिफारिश की जाती है, जिनका कि निर्धारित मात्रा और सिफारिश की गई विधियों से देने में मनुष्यों और पशुओं के स्वास्थ्य पर हानिकारक असर नहीं होता है।

कोटा सिटी ब्राउट एजेन्सी का बन्द होना

१२३१. श्री बरवा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा सिटी रेलवे ब्राउट एजन्सी बन्द कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री में० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). ठेकेदार ने गंभीर अनियमितताएं की थीं इसलिए १-७-६२ से ब्राउट एजेन्सी अस्थायी तौर पर बन्द कर दी गयी।

मेकांग अनुसन्धान परियोजना

१२३२. श्री बरवा : क्या सिचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टोनलेसेरा और मेकांग अनुसंधान परियोजना के क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिये कमीशन के दो अफसर मई, १९६१ में बैंकाक भेजे गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो जन, १९६२ तक प्रस्तुत उनकी रिपोर्ट का क्या व्यौरा है?

सिचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलमगेशन) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

विबरण

केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के अधिकारियों द्वारा अब तक दी गई रिपोर्टों का व्यौरा संक्षेप रूप में नीचे दिया जाता है :-

१. टोनले सैप बैरोज एक बहुत लाभप्रद परियोजना सिद्ध होगी, जो कि और चीजों के साथ साथ, मच्छलियों की पैदावार को बढ़ाएगी, शुष्क ऋतु में पानी के स्तर को थोड़ा बढ़ा कर बड़ी झील के सदा रहने को निश्चित सा कर देगी और निम्न डल्टा में बाढ़ शिखर में से १ से १॥ मीटर कम करने में सहायता देगी।

२. बैरोज के लिए दो वैकल्पिक स्थल हैं। स्थल का अन्तिम चुनाव विस्तृत क्षत्रीय अनुसन्धान, जो कि अब किया जा रहा है के बाद करना होगा।

प्रस्तावित स्थलों में से एक में उपस्तर को मोटे रूप से जानने के लिए अभी तक जांच के तीन निम्नलिखित तरीके उपयोग में लाये गये हैं :-

(१) वक्रीकरण भूकम्प विज्ञान द्वारा भू-भौतिकीय अध्ययन (Geophysical studies through refraction seismology)

(२) नग्न परीक्षण गर्त (Open trail pits) (ब्राउट)

(३) वाश-बोरिंग (दस)

३. जहां तक मच्छलियों पर अध्ययन का सम्बन्ध है, भारतीय दल बड़ी झील के सुधार के लिए पग उठाने के सम्बन्ध में

एक विस्तृत नोट तैयार कर रहा है। इस में मत्स्यग्रहण, झील को बनाए रखने की आवश्यकता तथा कुछ और तत्सम्बन्धी विषय भी सम्मिलित होंगे।

४. उपयुक्त निर्माण सामग्री को चुनने के लिए तथा उनका इंजीनियरी गुण जानने के वास्ते परीक्षण करने के लिए, कम्बोदिया में एक मिट्टी तथा कंक्रीट की प्रयोगशाला स्थापित करने का विचार है। भारत में मिलने वाले लगभग सारे सामान के लिए आर्डर दे दिये गये हैं।

५. कम्बोदिया और वीतनम के कुछ इंजीनियरों के लिये भारत में प्रशिक्षण सुविधाएं दी जा रही हैं।

भूचालीय इंजीनियरी

१२३३. श्री बंरवा : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भूचालीय क्षेत्रों में बांधों के निर्माण के काम की भूचालीय इंजीनियरी में हुई नवीन खोजों का अध्ययन करने के लिये केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के जल संभाग के जो सदस्य खास तौर पर जापान भेजे गये थे उनकी भूचालीय स्थल में बांधों के निर्माण के बारे में रिपोर्ट का क्या व्यौरा है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : महत्वपूर्ण व्यौरा सुझाव। निम्नलिखित हैं :—

(१) स्पन्दन सम्बन्धी तथा गत्यात्मक समस्याओं से और विशेषतया भूचालीय इंजीनियरी से सम्बद्ध अनुसन्धान निम्नलिखित प्रयोगशालाओं में करने पड़ते हैं :—

(अ) विधि विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं में।

(ब) इंजीनियरी महा विद्यालयों की प्रयोगशालाओं में।

(स) सिंचाई तथा विद्युत् की, डिफन्स, रेलवे और भवन अनुसन्धान, आदि की प्रयोगशालाओं में।

(२) नदी घाटी परियोजनाओं के क्षेत्र में, संरचनाओं के व्यवहार के निरीक्षण को रिकार्ड करने के लिए संरचनाओं में यंत्रों के अवस्थापन को सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय किये जायें।

(३) नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी से सलाह कर, निरीक्षणों के लिए आवश्यक 'स्ट्रेन गाजिज' तथा सम्बद्ध यंत्रों को बनाने के लिए पग उठाने चाहिए।

(४) विशिष्ट क्षेत्रों में काम करने वाले इंजीनियरों की टीमें जापान जैसे देशों में भेजी जानी चाहिए, ताकि वे भूचालीय इंजीनियरों के क्षेत्र में की गई प्रगति से अपना सम्बन्ध स्थापित रखें।

(५) गत्यात्मक प्रतिरूपों की सहायता से केन्द्रीय जल तथा विद्युत् गवेषण केन्द्र, पूना में अध्ययन शुरू करना चाहिए।

टिड्डी संकट

१२३४. श्री बंरवा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने टिड्डी दल को रोकने के लिये कितना रुपया तीनों योजनाओं में अब तक खर्च किया है;

(ख) देश में किन स्थानों पर टिड्डी संकट को रोकने में सफलता मिली है;

(ग) क्या दिनांक ७ जुलाई, १९६२ को मथुरा से कोसीकलां स्टेशन तक बड़ी तादाद में टिड्डी दल बैठा हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो उसको रोकने के लिए हमारे विशेषज्ञों ने क्या प्रयत्न किया ?

साख तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डा० राम सुभग सिंह) : (क)

रूपये

(१) पहली योजना .	१,०४,५२,२५६
(२) दूसरी योजना .	७०,२५,०४३
(३) तीसरी योजना .	६३
(क) १९६१-६२ .	२५,२२,५५५
(ख) १९६२-६३ .	२५,३०,६३६
(अनुमानित)	

(ख) निम्न राज्य टिड्डियों से प्रभावित हैं :—

धम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के संघीय क्षेत्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब ।

भारत में उसके पश्चिमी देशों से आने वाले विदेशी टिड्डी दलों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन भारत के नियत महसूल क्षेत्र और राज्यों में क्रमशः केन्द्रीय और राज्तीय टिड्डी विरोधी संगठनों ने टिड्डियों को बरबाद करने के लिए तुरन्त नियंत्रण उपाय किये हैं । उड़ते और बैठे हुए अनेक दलों को नष्ट कर दिया गया । सभी प्रभावित स्थानों में स्थिति भली प्रकार नियंत्रण में है । अंडों से बच्चे निकलते ही उनको नष्ट करने के लिए पर्याप्त प्रबन्ध किये हुए हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) राजस्व और अन्य विकास विभागों के स्थानीय कर्मचारियों के सहयोग से उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की वनस्पति रक्षा सेवा ने कीटनाशी दवाइयों के फुहारने और बुरकने के द्वारा बैठे टिड्डी दलों को बरबाद करने के तुरन्त उपाय किये ।

1531 (Ai) LSD—6.

भारतीय रेलवे में नियुक्तियां

१२३५. श्री कृष्ण देव त्रिपाठी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे आयुगों एवं अधिकारियों द्वारा भारतीय रेलों में काम करने के लिये कितने कर्मचारियों की नियुक्ति अप्रैल, १९५७ से मार्च, १९६२ तक की गई;

(ख) इन नियुक्तियों में कितने मुसलमान, एंग्लो-इण्डियन, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के व्यक्ति अलग-अलग संख्या में थे; और

(ग) उक्त अवधि में नियुक्त किये गये व्यक्तियों में भारत सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित जातियों की उपजातियों में से प्रत्येक के कितने व्यक्ति थे ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) (१) मुसलमानों के लिए कोई आरक्षण नहीं है ।

(२) एंग्लो-इण्डियनों के लिए जो आरक्षण निर्धारित था वह २६-१-१९६० से समाप्त हो गया । अप्रैल, १९५७ से २५ जनवरी १९६० तक की सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(३) अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(४) पिछड़े हुए वर्गों के लिए कोई आरक्षण नहीं है ।

(ग) जाति के आधार पर आंकाड़े नहीं रखे जाते ।

Bengal Flying Club

1236. Shri Karjee: Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that the Bengal Flying Club is going to be abolished very soon due

to malpractices, financial irregularities and shortage of funds;

(b) whether it is also a fact that the club was proposed to be shifted from Barrackpore to Behala for the sake of economy and construction of runways and hangars was started there in 1950, but the transfer could not be given effect to due to the objections of some of the office bearers;

(c) whether Government took any step at any time in the past to save the club from abolition and find out the causes of malpractices and financial irregularities; and

(d) if so, what were those steps and what was the result?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Communications (Shri Bhagavati): (a) As far as Government are aware, there is no proposal under consideration, to abolish the Bengal Flying Club.

(b) Yes, Sir, it was proposed to shift the Club from Barrackpore to Behala on operational grounds. Government is not aware of any objection from the office bearers of the Club to its shifting to Behala. The construction work at Behala was started only in 1959. The airfield is nearing completion and may be ready for operations after electricity and water supply have been made available.

(c) Certain irregularities in the affairs of this Club came to the notice of Government in the past, when necessary steps were taken to remedy the position.

(d) In the year 1950-51, Government came to know of mis-management and financial irregularities done at the Club. An officer of the Civil Aviation Department was specially deputed to check the Club's accounts on the spot and to investigate into the affairs of the Club. His investigation revealed that the then President of the Club was mainly responsible for these irregularities. A special Committee Meeting of the Club was thereafter arranged and the President of the Club was persuaded to resign from his post.

A new Managing Committee was appointed.

2. In the year 1955-56, certain financial irregularities were noticed by an officer of the Civil Aviation Department during the course of his inspection of the Club. These were immediately brought to the notice of the Managing Committee of the Club and they were directed to remove these irregularities and organise the Club properly. Payment of subsidy to the Club was also withheld for some time, but was released after the Club showed improvement.

3. In 1960-61, some irregularities in regard to the working of this Club came to notice. An officer of the Civil Aviation Department was specially deputed to investigate into the affairs of the Club. His investigation has revealed certain financial irregularities and fictitious logging of flying hours. Steps are now being taken, in consultation with the State Government, to re-organise the Club and provide for necessary safeguards against repetition of any financial irregularities in future.

Family Planning

1237. Shri Vishwa Nath Pandey: Will the Minister of Health be pleased to state:

(a) the steps that have been taken to associate village Panchayats in the work of family planning; and

(b) what arrangements have been made for distribution of contraceptives and literature on family planning at village level?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) and (b). Family Planning Orientation Camps each of three days' duration are held specially for lay people and village group leaders to create a background of acceptance of the family planning programme in the rural areas. Family Planning services are now being provided at every primary health centre and also three sub-centres attached to each primary health centre. Contracep-

tives are distributed free to all in the rural areas irrespective of the income of the individual. Literature on family planning is also supplied to each centre set up under the family planning programme.

अवकाश में विद्यार्थियों के लिये यात्रा सम्बन्धी सुविधायें

१२३८. श्री प्रकाशबीर शास्त्री : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छात्रों को अवकाश के दिनों में अपने घर तक आने-जाने के लिये अथवा किन्हीं यात्रा विशेषों पर आने-जाने के लिये विभाग की ओर से सुविधायें दी जाती हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह सुविधायें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था को ही दी जाती हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या कुछ ऐसी संस्थायें भी इसका लाभ प्राप्त कर रही हैं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनको किन विशेष स्थितियों में यह सुविधायें दी गयी और उन के नाम क्या हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (घ). जी हां, विद्यार्थियों को रियायती किराये पर टिकट दिये जाते हैं। मान्यताप्राप्त शिक्षा संस्थाओं के विद्यार्थियों को जो रियायत दी जाती है वह प्रत्येक मामले को ध्यान में रखते हुए, दूसरी अनमोदित संस्थाओं के विद्यार्थियों, प्रशिक्षार्थियों आदि को भी दी जाती है। इस समय जो संस्थाएं इन रियायतों के पाने की हकदार हैं, उन की एक पूरी सूची सभा पटल पर रखी जाती है [नेत्रिये परिशिष्ट संख्या २, अनुबन्ध संख्या २०]

C.H.S. Scheme in Delhi

1239. Shri Jagdev Singh Siddhanti: Will the Minister of Health be pleased to state:

(a) whether a large number of Central Government employees are residing in Bahadurgarh, a suburb of Delhi in Rohtak District;

(b) whether it is a fact that these employees do not enjoy the benefits of Contributory Health Service Scheme and if so, when Government intend to extend this Scheme to this area; and

(c) if not, what alternative medical facilities are proposed to be provided for these employees keeping in view the fact that the civil dispensary of that place is not well equipped?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) to (c). Bahadurgarh is situated at a distance of about 18 miles from Delhi and is outside the jurisdiction of the Union Territory of Delhi. It is understood that about 1,000 Central Government employees are residing in Bahadurgarh. Since it has not yet been possible to extend the C.H.S. Scheme to Central Government employees residing in places like Shahdara, Gandhi Nagar etc. which fall within the territorial jurisdiction of the Union Territory of Delhi, there is little prospect of the Scheme being extended to places outside Delhi, like Bahadurgarh, in the near future.

The Government of Punjab is primarily responsible for the provision of medical facilities to the residents of Bahadurgarh.

Tibbia Medical College, Delhi

1240. Shri Jagdev Singh Siddhanti: Will the Minister of Health be pleased to state:

(a) whether Government propose to take over Tibbia College of New Delhi under Maulana Azad Medical College;

(b) what steps have been taken to improve Ayurvedic system of Medicine in India;

(c) whether it will not be possible for Government to allow the degree holders from Tibbia College to complete condensed course of one year in M.B.B.S. Delhi;

(d) whether there is any proposal to make B.I.M.S. degree from Tibbia College equivalent to M.B.B.S. degree; and

(e) if so, how much time it will take to implement this proposal?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) The Government of India have received suggestions to take over the Tibbia College and develop it as a separate institution.

(b) A statement is placed on the Table of the House.

STATEMENT

(i) The Government of India have set up the Central Council of Ayurvedic Research to advise them on matters relating to the development of Ayurveda. The Council has formulated a curriculum of studies.

(ii) Financial assistance is being given for establishment of new institutions and/or upgrading of existing institution.

(iii) Research Units to conduct research on various aspects have been set up. It is proposed to set up more units in different institutions to conduct researches—clinical, chemical, pharmacological, pharmacognostical, fundamental, literary etc.

(iv) A Central Institute of Research in Indigenous Systems of Medicine and a Post Graduate Training Centre in Ayurveda have been set up at Jamnagar. It is proposed to set up more Research and Post Graduate Training Centres. Proposals to open such centres at Banaras and Poona are under examination.

(v) Establishment of herb gardens; land has been purchased at Poona.

(vi) Survey of Medical Plants: a Survey Unit has been sanctioned at Hardwar. Proposals for establishing more units are being examined.

(c) No. Sir.

(d) No.

(e) Does not arise.

Rural Water Supply in Rajasthan

1241. Dr. L. M. Singhvi: Will the Minister of Health be pleased to state:

(a) whether the Government of Rajasthan have submitted any comprehensive scheme for rural water supply in Rajasthan;

(b) if so, the details thereof;

(c) how many tube-wells and water tanks have been provided in different areas of Rajasthan for solving the acute problem of supply of drinking water;

(d) what is the percentage of total expenditure on rural water supply, which has been spent so far during the Second Five Year Plan and Third Five Year Plan for rural water supply in Jodhpur, Jaisalmer and Bikaner districts of Rajasthan; and

(e) what are the reasons for paying relatively scant attention to the problem of rural water supply in these districts which are the worst affected in the country?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) No comprehensive scheme for rural water supply has been received from the Government of Rajasthan. However, a few individual rural water supply and sanitation schemes have been approved during the I and II Five Year Plans.

(b) Does not arise in view of (a) above.

(c) to (e). Necessary information is being collected from the Government of Rajasthan and will be placed on the Table of the Sabha when received.

Wind Power Plants

1242. Shri Basumatari: Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have been negotiating with